NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TIMES OF INDIA, Delhi, 9.4.2025
Page No. 2, Size:(3.90)cms X (15.85)cms.

HC stays NHRC proceedings into KIIT Nepal student 'suicide'

Lalmohan Patnaik | TNN

Cuttack: Orissa HC has ordered a stay on all National Human Rights Commission proceedings related to the alleged suicide of a Nepalese student at KIIT deemed-to-be University on Feb 16. The HC has also suspended NHRC's March 27 order that held the university accountable for the incident, saying it violated principles of natural justice as KIIT was not given an opportunity to be heard.

Justice S K Panigrahi, while hearing a petition filed by Kalinga Institute of Industrial Technology, emphasised that adherence to principles of natural justice "is not a mere formality, but a foundational requirement" in quasi-judicial proceedings. "The absence of notice or denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates fairness of the process," the judge noted.

HC issued notice to NHRC to respond by April 26, with the next hearing for April 29.

The case involves a series of events leading to the tragic death of the Nepalese student. According to university submissions, the deceased had initially filed a complaint against a fellow student on Jan 12, regarding inappropriate photographs. Despite attempted resolutions and written undertakings between parties, the situation escalated, ultimately leading to the student's death.

MILLENNIUM POST, Delhi, 9.4.2025
Page No. 4, Size:(24.00)cms X (15.49)cms.

NHRC issues notices to states, UTs; seeks reports over issues of prisoners

NEW DELHI: Taking suo motu cognisance of difficulties being faced by prisoners including women inmates in various jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to chief secretaries of all the states and Union Territories, seeking reports within four weeks.

These problems include overcrowding, lack of basic amenities and healthcare facilities in jails, the NHRC said in a statement. "The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails across the country, as well as the complaints," it said. The Commission said it has issued notices to the chief secretaries of all the states and Union Territories (UTs) seeking a report from them in four weeks, which should include various details.

These include the number of women prisoners lodged in jails in a state, the number of women prisoners whose babies are lodged in jails on account of the mothers being incarcerated, the number of women prisoners who are convicted prisoners and those who are undertrial prisoners, number of women undertrial prisoners who are languishing for more than a year in jail, and number of male undertrial prisoners and those who are languishing in jail for more than a year, the statement said.

Some other concerns raised include the violation of the rights to dignity and safety of women prisoners, increased violence against them causing mental distress, unhygienic conditions without adequate toilets, sanitary napkins and clean drinking water facilities, it said. AGENCIES

V

HINDU, Delhi, 9.4.2025
Page No. 10, Size:(2.99)cms X (8.88)cms.

NHRC notice on hardship faced by prisoners

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Taking *suo motu* cognisance of various difficulties being faced by prisoners, including women inmates and their children in jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notice to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories seeking replies on the issue.

The commission says it is concerned over the lack of basic amenities and healthcare facilities in jails along with overcrowding in prisons.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 9.4.2025
Page No. 13, Size:(8.37)cms X (10.94)cms.

buzz

NHRC presents awards to the seven winners of its short films competition

NHRC organised a function at its premises in New Delhi to felicitate and present awards to the seven winners of its short film competition on human rights in 2024. Addressing the gathering, Justice V Ramasubramanian, Chairperson, NHRC, India, said that the objective of the Commission is to create awareness to promote and protect human rights.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 9.4.2025
Page No. 13, Size:(8.47)cms X (9.17)cms.

NHRC, India takes action against reported death of a nursing student

The National Human Rights Commission took suo moto cognisance of a media report that on March 22, a third year Nursing student died after three months in coma, following a suicide attempt in the hostel room amidst allegations of harassment by the warden on in Kasaragod district of Kerala. The Commission is seeking further investigation in the matter.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 9.4.2025
Page No. 13, Size:(8.70)cms X (9.09)cms.

NHRC, India takes suo moto cognisance of a reported murder

The National Human Rights Commission (NHRC) took suo moto cognisance of a media report that a retired Sub-Inspector of Police was murdered in broad daylight in the Tirunelveli district of Tamil Nadu by a group of four persons. Notices have been issued to the concerned authorities calling for a detailed report.

JANSATTA, Delhi, 9.4.2025
Page No. 2, Size:(8.02)cms X (7.01)cms.

कैदियों की परेशानियों को लेकर मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों से मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अप्रैल।

देश भर की जेलों में रहने वाले कैदियों की परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। इन कैदियों में महिलाएं और उनके बच्चे भी हैं।

आयोग ने मुख्य सचिवों से चार हफ्ते के भीतर यह बताने को कहा है कि जेलों में कुल कितनी महिला कैदी हैं। इनमें बच्चों सहित रह रही महिला कैदी कितनी हैं। सजायाफ्ता व विचाराधीन महिला कैदियों की अलग-अलग संख्या बताने का भी आयोग ने निर्देश दिया है। आयोग ने जेलों में एक साल से ज्यादा समय से रह रहे महिला और पुरूष दोनों कैदियों का ब्यौरा भी तलब किया है।

आयोग ने अपनी तरफ से खुद पहल करते हुए इस मामले में कदम उठाया है। कैदियों को जेलों में कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मसलन क्षमता से ज्यादा संख्या में कैदी होना व जरूरी बुनियादी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आदि। आयोग को इस बारे में समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से शिकायतें और जानकारियां मिलती रही हैं।

आयोग की चिंता महिला कैदियों की सुरक्षा व गरिमा के अधिकार के हनन को लेकर भी है। जेलों में शौचालयों जैसी सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं हैं। साफ पेयजल को लेकर भी शिकायतें मिलती हैं। कैदियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की संतोषजनक व्यवस्था न होना भी एक मुद्दा है।

आयोग की चिंता महिला कैदियों की सुरक्षा व गरिमा के अधिकार के हनन को लेकर भी है। जेलों में शौचालयों जैसी सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं हैं। साफ पेयजल को लेकर भी शिकायतें मिलती हैं। खराब भोजन तो आम बात है। कैदियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की संतोषजनक व्यवस्था न होना भी एक मुद्दा है।

जनसत्ता Wed, 09 April 2025
https://epaper.jansatta.com/c/77140681

AMAR UJALA, Delhi, 9.4.2025
Page No. 13, Size:(6.44)cms X (4.59)cms.

कैदियों की समस्याओं पर मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे नोटिस

भीड़भाड़, बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। देश भर की जेलों में कैदियों, विशेषकर महिला बंदियों की समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए हैं।

आयोग ने जेलों में भीड़भाड़, बुनियादी सुविधाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवा के अभाव जैसे मुद्दों पर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एक बयान में आयोग ने कहा कि यह कदम विशेष निगरानीकर्ताओं खबरों और शिकायतों के आधार पर उठाया गया। इन्होंने विभिन्न जेलों का दौरा कर समस्याओं का जायजा लिया था। आयोग ने राज्यों से मांगा है कि वे अपनी रिपोर्ट में राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या, जेलों में माताओं के साथ रह रहे शिशुओं की संख्या, दोषसिद्ध और अंडरट्रायल महिला कैदियों का ब्यौरा, एक साल से अधिक समय से जेल में बंद विचाराधीन महिलाओं की संख्या, पुरुष विचाराधीन कैदियों और उनकी अवधि का विवरण मांगा है। आयोग ने कहा कि यह मुद्दे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन से जुड़े हैं। एजेंसी

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 9.4.2025
Page No. 03, Size:(2.92)cms X (8.31)cms.

देश में महिला कैदियों की कठिनाइयों पर राज्यों को एनएचआरसी का नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देशभर की विभिन्न जेलों में बंद महिला कैदियों और उनके बच्चों को हो रही कठिनाइयों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट भेजने को कहा है। राज्यों को रिपोर्ट में महिला कैदियों और शिशुओं के साथ रहने वाली महिला कैदियों, दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों के साथ ही एक साल से ज्यादा समय से जेलों में बंद महिला और पुरुष विचाराधीन कैदियों की संख्या भी बतानी होगी।

एनएचआरसी के विशेष मानीटर्स ने देशभर की विभिन्न जेलों का दौरा कर जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव आदि रिपोर्ट दी थी। इसमें महिला कैदियों के सम्मान और सुरक्षा के अधिकारों के उल्लंघन, पर्याप्त शौचालय, सैनेटरी नैपकिन, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं का अभाव तथा खराब गुणवत्ता वाला भोजन का मुद्दा भी उठाया गया था।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 9.4.2025
Page No. 11, Size:(2.02)cms X (6.67)cms.

महिला कैदियों की कठिनाइयों पर राज्यों को नोटिस जारी किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेलों में बंद महिला कैदियों व उनके बच्चों को हो रही कठिनाइयों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट भेजने को कहा है। राज्यों को रिपोर्ट में महिला कैदियों व शिशुओं के साथ रहने वाली महिला कैदियों, दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों के साथ ही एक साल से ज्यादा समय से जेलों में बंद महिला और पुरुष विचाराधीन कैदियों की संख्या भी बतानी होगी।

आयोग के विशेष मानीटर्स ने देशभर की जेलों का दौरा कर रिपोर्ट दी थी, जिसमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने, बुनियादी सुविधाओं व स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया गया था। रिपोर्ट देखकर आयोग ने महिला कैदियों की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया है।

NEW INDIAN EXPRESS, Bhubaneswar, 9.4.2025
Page No. 3, Size:(24.90)cms X (23.92)cms.

HC stays NHRC order, proceedings in Nepalese student death case

EXPRESS NEWS SERVICE @Cuttack

IN a significant development, the Orissa High Court has issued a stay on the order of the National Human Rights Commission (NHRC) as well as all its proceedings on the case of alleged suicide by a Nepalese student at KIIT University on February 16.

The NHRC in its order on March 27 had held KIIT accountable for the death of the student and directed the state chief secretary to submit an action taken report within four weeks.

"The commissioner of police, Bhubaneswar-Cuttack, is directed to submit updated investigation report. Let the chairman, UGC, New Delhi, consider initiating requisite action against the KIIT University," the order also stated.

The HC issued the stay on Monday on a petition filed by KIIT and KISS challenging the NHRC order. While issuing notice to NHRC to reply by April 26, the single judge bench of Justice SK Panigrahi said, "It must be underscored that when orders are passed by quasi-judicial authorities, adherence to the principles of natural justice is not a mere formality but a foundational requirement. The absence of notice or the denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates the fairness of the process."

> **Absence of notice or the denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates the fairness of the process**
>
> Justice SK Panigrahi

"As an interim measure, it is directed that all further proceedings in the case, presently pending before the NHRC, shall remain stayed until the next date of listing of this matter (April 29). The operation and effect of the impugned order dated March 27, 2025, passed in the aforesaid case, shall also remain stayed until the matter is next taken up by this court," he specified.

Justice Panigrahi also directed the state government, Khurda collector, commissioner of police, and chairman UGC to refrain from taking any further steps or action pursuant to NHRC order until the next date.

The NHRC had observed that there was gross negligence and omission by the university authorities which resulted in suicide by the girl.

According to submissions recorded in the HC order, it was argued on behalf of KIIT that although officials of NHRC undertook an inquiry and subsequently prepared a report, neither the said report nor its findings were made available to the authorities of the petitioners' institution prior to the issuance of the impugned order on March 27.

While NHRC took cognisance of the matter on March 3, the Supreme Court had in the case of Amit Kumar vs Union of India on March 24 also taken note of the incident in KIIT University along with certain other similar incidents in the colleges across India. The Supreme Court has also formed a National Task Force on the issue. Therefore, NHRC ought to have shown some restraint before passing the impugned order, it was argued on behalf of KIIT.

PIONEER, Hyderabad, 9.4.2025
Page No. 5, Size:(18.02)cms X (18.57)cms.

NHRC seeks reports over issues faced by prisoners

Taking suo motu cognisance of difficulties being faced by prisoners including women inmates in various jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to chief secretaries of all the states and Union Territories, seeking reports within four weeks. These problems include overcrowding, lack of basic amenities and healthcare facilities in jails, the NHRC said in a statement. "The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails across the country, as well as the complaints," it said .The Commission said it has issued notices to the chief secretaries of all the states and Union Territories (UTs) seeking a report from them in four weeks, which should include various details.

PIONEER, Hyderabad, 9.4.2025
Page No. 5, Size:()cms X ()cms.

MP: Five-day police custody for 'fake' cardiologist

A court in Madhya Pradesh's Damoh on Tuesday remanded alleged fake cardiologist, Narendra John Camm, linked to the death of seven patients, to police custody for five days. A day earlier, he was arrested in Prayagraj, Uttar Pradesh. "Chief Judicial Magistrate Sneha Singh remanded Camm to police custody for five days on our request," Public Prosecutor Satish Kapasya told PTI. Police had registered a First Information Report (FIR) against Camm amid allegations that he possesses a bogus medical degree on charges of forgery and dishonest misappropriation on a complaint lodged by Damoh district's Chief Medical and Health Officer (CMHO) MK Jain. Damoh Superintendent of Police (SP) Shrut Kirti Somwanshi had said the accused would be interrogated on questions raised by the CMHO in his complaint. "In the original complaint (submitted to NHRC), there was a mention of the death of seven patients at Mission Hospital.

PIONEER, Vijayawada, 9.4.2025
Page No. 5, Size:(15.24)cms X (24.54)cms.

MP: Five-day police custody for 'fake' cardiologist

A court in Madhya Pradesh's Damoh on Tuesday remanded alleged fake cardiologist, Narendra John Camm, linked to the death of seven patients, to police custody for five days. A day earlier, he was arrested in Prayagraj, Uttar Pradesh. "Chief Judicial Magistrate Sneha Singh remanded Camm to police custody for five days on our request," Public Prosecutor Satish Kapasya told PTI. Police had registered a First Information Report (FIR) against Camm amid allegations that he possesses a bogus medical degree on charges of forgery and dishonest misappropriation on a complaint lodged by Damoh district's Chief Medical and Health Officer (CMHO) MK Jain. Damoh Superintendent of Police (SP) Shrut Kirti Somwanshi had said the accused would be interrogated on questions raised by the CMHO in his complaint. "In the original complaint (submitted to NHRC), there was a mention of the death of seven patients at Mission Hospital.

PIONEER, Vijayawada, 9.4.2025
Page No. 5, Size:(18.02)cms X (18.57)cms.

NHRC seeks reports over issues faced by prisoners

Taking suo motu cognisance of difficulties being faced by prisoners including women inmates in various jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to chief secretaries of all the states and Union Territories, seeking reports within four weeks. These problems include overcrowding, lack of basic amenities and healthcare facilities in jails, the NHRC said in a statement. "The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails across the country, as well as the complaints," it said .The Commission said it has issued notices to the chief secretaries of all the states and Union Territories (UTs) seeking a report from them in four weeks, which should include various details.

HINDU, Kochi, 9.4.2025
Page No. 12, Size:(2.35)cms X (6.88)cms.

NHRC notice on hardship faced by prisoners

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Taking *suo motu* cognisance of various difficulties being faced by prisoners, including women inmates and their children in jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notice to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories seeking replies on the issue.

The commission says it is concerned over the lack of basic amenities and healthcare facilities in jails along with overcrowding in prisons.

HINDU, Hyderabad, 9.4.2025
Page No. 8, Size:(2.21)cms X (6.88)cms.

NHRC notice on hardship faced by prisoners

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Taking *suo motu* cognisance of various difficulties being faced by prisoners, including women inmates and their children in jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notice to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories seeking replies on the issue.

The commission says it is concerned over the lack of basic amenities and healthcare facilities in jails along with overcrowding in prisons.

HINDU, Chennai, 9.4.2025
Page No. 12, Size:(2.49)cms X (6.97)cms.

NHRC notice on hardship faced by prisoners

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Taking *suo motu* cognisance of various difficulties being faced by prisoners, including women inmates and their children in jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notice to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories seeking replies on the issue.

The commission says it is concerned over the lack of basic amenities and healthcare facilities in jails along with overcrowding in prisons.

TIMES OF INDIA, Kochi, 9.4.2025
Page No. 7, Size:(3.66)cms X (15.37)cms.

Orissa HC stays NHRC proceedings

Lalmohan Patnaik
@timesofindia.com

Cuttack: The Orissa high court has ordered a stay on all National Human Rights Commission (NHRC) proceedings related to the alleged suicide of a Nepalese student at KIIT deemed-to-be University on Feb 16. The court has also suspended NHRC's March 27 order that held the university accountable for the incident, saying it violated principles of natural justice as KIIT was not given an opportunity to be heard.

KIIT STUDENT SUICIDE CASE

Justice S K Panigrahi, while hearing a petition filed by Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) and Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), emphasised that adherence to principles of natural justice "is not a mere formality, but a foundational requirement" in quasi-judicial proceedings. "The absence of notice or the denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates the fairness of the process," the judge noted.

The court has issued notice to NHRC to respond by April 26, with the next hearing scheduled for April 29.

The case involves a series of events leading to the tragic death of the Nepalese student.

TIMES OF INDIA, Chennai, 9.4.2025
Page No. 12, Size:(3.68)cms X (12.05)cms.

KIIT student 'suicide': Orissa HC stays NHRC proceedings

Cuttack: Orissa high court has ordered a stay on all National Human Rights Commission (NHRC) proceedings related to the alleged suicide of a Nepalese student at KIIT deemed-to-be University on Feb 16, reports **Lalmohan Patnaik**.

The court has also suspended NHRC's March 27 order that held the university accountable for the incident, saying it violated principles of natural justice as KIIT was not given an opportunity to be heard. Justice S K Panigrahi, while hearing a petition filed by Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) and Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), emphasised that adherence to principles of natural justice "is not a mere formality, but a foundational requirement" in quasi-judicial proceedings.

"The absence of notice or denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates the fairness of the process," the judge noted.

HITAVADA, Raipur, 9.4.2025
Page No. 2, Size:(24.90)cms X (9.79)cms.

DAMOH DEATHS

'Fake' doctor nabbed from Prayagraj

NHRC team registers statements of two people, further statements are expected to be registered on April 9

■ Staff Reporter

DAMOH police have succeeded in apprehending Dr Narendra John Camm from Prayagraj in Uttar Pradesh, who was absconding after the deaths of seven heart patients at Missionary Hospital in Damoh. The arrest was confirmed by Damoh SP Shrut Kirti Somvanshi, who said that search teams had been deployed in several locations, including Prayagraj.

Earlier, Damoh's Chief Medical and Health Officer (CMHO) Mukesh Jain filed an FIR against Dr Narendra John Camm late Sunday night while two other persons have also been named in the case.

The controversy erupted following claims that seven patients died after undergoing heart surgeries performed by Dr Camm, who allegedly practiced medicine using fake degrees. Investigations revealed that he carried out angiographies and angioplasties, which were linked to the patients' deaths.

On the other hand, a team from the National Human Rights Commission (NHRC) comprising Rinkle Kumar, Brajveer Kumar and Rajendra Singh, visited Damoh on Monday to investigate the matter. Only two individuals appeared before the team named Nabi Beg, son of deceased patient Raheesa Begum and complainant Krishna Patel. The team also met with Collector, SP and CMHO to gather more information. Further statements are expected to be registered on April 9. The team also visited Missionary Hospital as part of its inquiry.

Emphasising Government's zero-tolerance policy, Chief Minister Mohan Yadav assured further action will be taken without delay in the Damoh fake doctor scandal. Moreover, the Health Department has been asked to unfold any other cases of same nature. The accused using fake documents conducted multiple surgeries at a Missionary Hospital and some of the patients lost their lives allegedly after the treatment.

Chief Minister Yadav said "In the incident which came to light in Damoh, our Government is taking strict action. We do not delay action against such cases."

TIMES OF INDIA, Bhopal, 9.4.2025
Page No. 13, Size:(3.97)cms X (15.90)cms.

HC stays NHRC proceedings into KIIT Nepal student 'suicide'

Lalmohan Patnaik | TNN

Cuttack: Orissa HC has ordered a stay on all National Human Rights Commission proceedings related to the alleged suicide of a Nepalese student at KIIT deemed-to-be University on Feb 16. The HC has also suspended NHRC's March 27 order that held the university accountable for the incident, saying it violated principles of natural justice as KIIT was not given an opportunity to be heard.

Justice S K Panigrahi, while hearing a petition filed by Kalinga Institute of Industrial Technology, emphasised that adherence to principles of natural justice "is not a mere formality, but a foundational requirement" in quasi-judicial proceedings. "The absence of notice or denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates fairness of the process," the judge noted.

HC issued notice to NHRC to respond by April 26, with the next hearing for April 29.

The case involves a series of events leading to the tragic death of the Nepalese student. According to university submissions, the deceased had initially filed a complaint against a fellow student on Jan 12, regarding inappropriate photographs. Despite attempted resolutions and written undertakings between parties, the situation escalated, ultimately leading to the student's death.

EARLY TIMES, Jammu, 9.4.2025
Page No. 12, Size:(11.54)cms X (3.00)cms.

NHRC issues notices to states, UTs; seeks reports over issues faced by prisoners

AGENCIES

NEW DELHI, Apr 8: Taking suo motu cognisance of difficulties being faced by prisoners including women inmates in various jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to chief secretaries of all the states and Union Territories, seeking reports within four weeks.

These problems include overcrowding, lack of basic amenities and healthcare facilities in jails, the NHRC said in a statement.

"The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails across the country, as well as the complaints," it said.

The Commission said it has issued notices to the chief secretaries of all the states and Union Territories (UTs) seeking a report from them in four weeks, which should include various details.

These include the number of women prisoners lodged in jails in a state, the number of women prisoners whose babies are lodged in jails on account of the mothers being incarcerated, the number of women prisoners who are convicted prisoners and those who are undertrial prisoners, number of women undertrial prisoners who are languishing for more than a year in jail, and number of male undertrial prisoners and those who are languishing in jail for more than a year, the statement said.

Some of the other concerns raised include the violation of the rights to dignity and safety of the women prisoners, increased violence against them causing mental distress, unhygienic conditions without adequate toilets, sanitary napkins and clean drinking water facilities, it said.

ORISSA POST, Bhubaneswar, 9.4.2025
Page No. 8, Size:(19.67)cms X (5.82)cms.

NHRC takes suo motu cognisance of prisoners' plight

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, April 8: Taking suo motu cognisance of difficulties being faced by prisoners including women inmates in various jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to chief secretaries of all the states and Union Territories, seeking reports within four weeks.

These problems include overcrowding, lack of basic amenities and healthcare facilities in jails, the NHRC said in a statement. "The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails across the country, as well as the complaints," it said. The Commission said it has issued notices to the chief secretaries of all the states and Union Territories (UTs) seeking a report from them in four weeks, which should include various details.

These include the number of women prisoners lodged in jails in a state, the number of women prisoners whose babies are lodged in jails on account of the mothers being incarcerated, the number of women prisoners who are convicted prisoners and those who are undertrial prisoners, number of women undertrial prisoners who are languishing for more than a year in jail, and number of male undertrial prisoners and those who are languishing in jail for more than a year, the statement said.

These problems include overcrowding, lack of basic amenities and healthcare facilities in jails

Some of the other concerns raised include the violation of the rights to dignity and safety of the women prisoners, increased violence against them causing mental distress, unhygienic conditions without adequate toilets, sanitary napkins and clean drinking water facilities, it said.

Also, other concerns include poor quality food resulting in malnourishment, particularly in the case of pregnant women and lactating mothers, lack of educational opportunities for the children of women prisoners living in jails with them, non-implementation of their welfare programmes including legal aid, vocational training and rehabilitation, the statement said.

TIMES OF INDIA, Kolkata, 9.4.2025
Page No. 14, Size:(3.62)cms X (15.57)cms.

KIIT student suicide: HC stays NHRC proceedings

Lalmohan Patnaik | TNN

Cuttack: Orissa High Court has ordered a stay on all National Human Rights Commission proceedings related to the alleged suicide of a Nepalese student at KIIT deemed-to-be University on Feb 16. The high court has also suspended NHRC's March 27 order that held the university accountable for the incident, saying it violated principles of natural justice as KIIT was not given an opportunity to be heard.

Justice S K Panigrahi, while hearing a petition filed by Kalinga Institute of Industrial Technology, emphasised that adherence to principles of natural justice "is not a mere formality, but a foundational requirement" in quasi-judicial proceedings. "The absence of notice or denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates fairness of the process," the judge noted. HC issued notice to NHRC to respond by April 26, with the next hearing for April 29. According to university submissions, the deceased had initially filed a complaint against a fellow student on Jan 12, regarding inappropriate photographs. KIIT authorities argued they were not provided with the inquiry report or findings before the order was issued.

POLITICAL & BUSINESS DAILY, Bhubaneswar, 9.4.2025
Page No. 5, Size:(16.97)cms X (10.57)cms.

Orissa HC stays NHRC actions against KIIT over Nepalese student's death

PBD BUREAU/PTI

CUTTACK, APR 8

THE Orissa High Court has stayed till the next date of hearing the proceedings of the National Human Rights Commission (NHRC) against the Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) over a Nepalese student's death in February.

While hearing a petition by the KIIT, the single-judge bench of Justice Sanjeeb Kumar Panigrahi also ruled that no further actions could be taken against the private deemed to be university here till the court takes up the matter for further hearing on April 29.

The court also issued notices to all parties involved, including the NHRC, and directed them to submit their replies within three weeks.

The 20-year-old Nepalese woman's body was recovered from her hostel room inside the KIIT campus on February 16 following which tension mounted and students from the Himalayan nation were assaulted and forcibly evicted after they staged protests. The incident had raised a nation-wide outrage and the prime minister of Nepal also intervened in the matter.

Finding gross negligence on the part of the KIIT authorities over the "suicide", the NHRC on March 27 sought an action taken report from the Odisha government, UGC and the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) within four weeks.

In its petition, the KIIT argued that while the NHRC had taken suo motu cognisance of the student's death on March 3, it proceeded to issue directions on March 27 without notifying or seeking a response from the institution.

The KIIT submitted that this move violated the principles of natural justice, as the institute was not allowed to present its side.

The court, acknowledging the procedural lapse raised by the petitioner, in its order on Monday said that as an interim measure, directed that all further proceedings in the case, presently pending before the NHRC, shall remain stayed until the next date of listing of this matter.

POLITICAL & BUSINESS DAILY, Bhubaneswar, 9.4.2025
Page No. 7, Size:(8.27)cms X (11.32)cms.

NHRC takes suo motu cognizance of prisoners' plight, issues notices to all states and Union Territories

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the grave issues faced by prisoners, particularly women inmates and their children, in jails across the country. In a significant move to address the systemic challenges in the prison system, the NHRC has issued notices to the Chief Secretaries of all States and Union Territories, calling for comprehensive reports on the situation within four weeks.

The NHRC's intervention comes in response to numerous reports and complaints raised by its Special Monitors and Rapporteurs after their visits to various jails across India. The reports highlighted several pressing issues, including overcrowding, a lack of basic amenities, and inadequate healthcare facilities in prisons. These issues are compounded for women prisoners, who face unique challenges regarding safety, dignity, and health.

TIMES OF INDIA, Mumbai, 9.4.2025
Page No. 16, Size:(3.90)cms X (15.85)cms.

HC stays NHRC proceedings into KIIT Nepal student 'suicide'

Lalmohan Patnaik | TNN

Cuttack: Orissa HC has ordered a stay on all National Human Rights Commission proceedings related to the alleged suicide of a Nepalese student at KIIT deemed-to-be University on Feb 16. The HC has also suspended NHRC's March 27 order that held the university accountable for the incident, saying it violated principles of natural justice as KIIT was not given an opportunity to be heard.

Justice S K Panigrahi, while hearing a petition filed by Kalinga Institute of Industrial Technology, emphasised that adherence to principles of natural justice "is not a mere formality, but a foundational requirement" in quasi-judicial proceedings. "The absence of notice or denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates fairness of the process," the judge noted.

HC issued notice to NHRC to respond by April 26, with the next hearing for April 29.

The case involves a series of events leading to the tragic death of the Nepalese student. According to university submissions, the deceased had initially filed a complaint against a fellow student on Jan 12, regarding inappropriate photographs. Despite attempted resolutions and written undertakings between parties, the situation escalated, ultimately leading to the student's death.

HINDU, Mumbai, 9.4.2025
Page No. 10, Size:(2.39)cms X (6.87)cms.

NHRC notice on hardship faced by prisoners

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Taking *suo motu* cognisance of various difficulties being faced by prisoners, including women inmates and their children in jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notice to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories seeking replies on the issue.

The commission says it is concerned over the lack of basic amenities and healthcare facilities in jails along with overcrowding in prisons.

HINDU, Mumbai, 9.4.2025
Page No. 4, Size:(9.63)cms X (7.18)cms.

M.P. court sends 'fake' cardiologist to five-day police remand; 1 more impostor doctor surfaces

Mehul Malpani
BHOPAL

A cheating case has been filed against Shubham Awasthi, who had also served as BJP Jabalpur medical cell's co-convener

A court in Madhya Pradesh's Damoh district on Tuesday sent alleged impostor Narendra John Camm, linked to the death of seven patients, to five days police remand.

Mr. Camm is accused of posing as a doctor at Damoh's Mission Hospital and performing crucial surgeries like angioplasty and angiography, and causing at least seven deaths. An FIR was filed against him on Sunday night based on a report by a probe committee, which had been constituted by Damoh Collector Sudhir Kochhar after the first complaint received against him in February.

Speaking to *The Hindu*, Damoh Additional Superintendent of Police Sandeep Mishra said the investigating team is currently interrogating the accused in detail and trying to verify his alleged involvement in the complaints received so far.

Around 1.45 a.m. on Tuesday, a team arrived in Damoh after arresting the accused from Prayagraj in Uttar Pradesh following which he was presented before the district court.

Damoh SP (City) Abhishek Tiwari said a team led by Chief Medical and Health Officer (CMHO) Dr. Mukesh Kumar Jain is contacting the hospital management and staff, and the patients allegedly treated by him.

"While the police are currently focusing on the use of forged documents and if he actually stole a doctor's identity, we will also contact the universities and institutes concerned to get more details on his claims," he said. According to the FIR, during preliminary investigation, his documents were found to be "forged" and details like registration numbers "missing" from them.

A National Human Rights Commission team, which has been camping in Damoh since Monday, said it is probing multiple aspects involving alleged malpractices at the hospital and district medical administration.

Meanwhile, police have registered a cheating case against an another alleged bogus doctor, who had also served as BJP Jabalpur medical cell's co-convener, after a complaint that he worked in a government hospital on a fake degree. The case against Shubham Awasthi was registered on April 5. "An FIR of cheating has been registered against Shubham Awasthi, who has been accused of using a fake Ayush degree and working in government-run Seth Govind Das District Hospital, Jabalpur. The case was filed on the basis of a court order," Inspector Nehru Singh Khandate of Civil Lines police station said.

(With inputs from PTI)

FREE PRESS JOURNAL, Mumbai, 9.4.2025
Page No. 23, Size:(11.95)cms X (6.46)cms.

Show cause notice to Apollo Bilaspur in fake Dr John Camm case

Fake Doctor Accused in Multiple Deaths Arrested

Staff Reporter
BILASPUR

In a shocking turn of events, the Chief Medical Officer (CMO) of Bilaspur has issued a show-cause notice to Apollo Hospital, Bilaspur, demanding an explanation for the appointment of Dr. Narendra Vikramaditya Yadav, an alleged fake doctor accused of multiple deaths including the death of Chhattisgarh's first speaker. Dr. Yadav, also known as Narendra John Camm, has been implicated in the deaths of seven heart patients at Mission Hospital in Damoh, Madhya Pradesh, and is suspected of causing several fatalities in Bilaspur.

The controversy gained momentum after Prof. Pradeep Shukla, son of the late Rajendra Prasad Shukla, the first Speaker of the Chhattisgarh Assembly, alleged that his father died due to a surgery performed by Dr. Yadav. According to Prof. Shukla, his father was admitted to Apollo Hospital in August 2006 for heart treatment, where Dr. Yadav conducted an angiography using laser technology. Following the procedure, the former Speaker's health deteriorated, and he passed away after 18 days on a ventilator.

Prof. Shukla further claimed that subsequent investigations by the Indian Medical Association (IMA) revealed that Dr. Yadav's medical degree was fake. The CMO, Dr. Pramod Tiwari, has now sought documentary evidence of Dr. Yadav's qualifications and the grounds for his appointment at Apollo Hospital.

Notably, then Chief Minister Dr. Raman Singh and Assembly Speaker Prem Prakash Pandey had instructed that all possible treatments be provided to the late Speaker without financial concerns. The then Collector, Gaurav Dwivedi, also visited the hospital during the treatment.

Dr. Yadav, who hails from Kanpur, claims to hold an MBBS degree from a medical college in Andhra Pradesh, with registration number 153427. However, his subsequent MD and cardiology degrees from Kolkata, Darjeeling, and the UK lack valid registration numbers. He was employed at Apollo Hospital in 2006.

The case took a darker turn recently when it was revealed that Dr. Yadav, operating under the alias Dr. N John Camm, performed 15 heart surgeries at Mission Hospital in Damoh between December 2024 and February 2025. Seven patients reportedly died during this period. Following these revelations, Dr. Yadav escaped but was apprehended in Prayagraj on Monday. The National Human Rights Commission has taken serious note of the incident.

Authorities are now investigating the full extent of Dr. Yadav's fraudulent activities and the systemic lapses that allowed him to practice medicine without valid credentials.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TIMES OF INDIA, Chandigarh, 9.4.2025
Page No. 18, Size:(3.84)cms X (13.24)cms.

HC stays NHRC proceedings into KIIT Nepal student 'suicide'

Lalmohan Patnaik | TNN

Cuttack: Orissa HC has ordered a stay on all National Human Rights Commission proceedings related to the alleged suicide of a Nepalese student at KIIT deemed-to-be University on Feb 16. The HC has also suspended NHRC's March 27 order that held the university accountable for the incident, saying it violated principles of natural justice as KIIT was not given an opportunity to be heard.

Justice S K Panigrahi, while hearing a petition filed by Kalinga Institute of Industrial Technology, emphasised that adherence to principles of natural justice "is not a mere formality, but a foundational requirement" in quasi-judicial proceedings. "The absence of notice or denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates fairness of the process," the judge noted.

HC issued notice to NHRC to respond by April 26, with the next hearing for April 29.

The case involves a series of events leading to the tragic death of the Nepalese student.

HINDUSTAN TIMES, Jammu, 9.4.2025
Page No. 4, Size:(12.46)cms X (11.54)cms.

{ MADHYA PRADESH }

'Fake' doc involved in deaths of 7 held

Shruti Tomar
letters@hindustantimes.com

BHOPAL/SAGAR: Madhya Pradesh Police on Monday arrested a man who is accused of forging his medical degrees operating on patients in a hospital in Damoh district, allegedly leading to the deaths of at least seven people.

The arrest came on a day the police filed a first information report against the man – identified by the police as Narendra John Camm – under sections 318 (cheating), 338 (forgery of valuable securities, wills, and other important documents), 336 (forgery, specifically creating or altering documents or electronic records with the intent to deceive or cause harm) and 340(2) (using a forged document or electronic record as genuine) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and under the MP Ayurvedic Council Act.

Damoh superintendent of police Shrutkirti Somvanshi confirmed the arrest from Prayagraj. "After the registration of the FIR, our cyber team got active as this doctor, who is known as Narendra Yadav or Narendra John Camm, had a habit of running away from one place to another. We got input from cyber team and Damoh police nabbed him from Drona Omaxe township in Prayagraj and he is now being brought to Damoh," said the SP.

Narendra John Camm

The developments came days after the National Human Rights Commission (NHRC) initiated a probe into the deaths of seven people at Mission Hospital in the Damoh district.

On Sunday night, Damoh chief medical and health officer MK Jain filed a complaint with the police, alleging that "Dr. Narendra John Camm" committed fraud by doing angiography and angioplasty in Mission Hospital without registering with the Madhya Pradesh Medical Council. "They didn't find the registration of Dr. Narendra John Camm on the medical documents, which appears suspicious at first sight. They also found forgery in his degrees," said Somvanshi. The matter of the deaths is still being investigated by the district administration and the NHRC, and sections related to the deaths might be added later based on the findings.

An investigation team including district vaccination officer Vishal Shukla, district health officer Vikrant Singh Chauhan, and CMHO Jain were formed to investigate the case in Mission Hospital, Damoh, Jain said. The probe team was formed on April 5. The team did not find Dr. Narendra John Camm in Mission Hospital and the manager told the team that he had left the job, it added.

"The manager provided the documents related to the degree of Dr. Narendra John Camm, in which the investigation team prima facie did not find the registration number of the medical council/ university mentioned in the degrees of the concerned doctor, which is generally mentioned in the documents of all universities and medical councils," the FIR seen by HT said.

"The documents presented by Mission Hospital of Dr. Narendra John Camm, his medical registration, certificate has been issued by Andhra Pradesh Medical Council, but till date, the name of Dr. Narendra John Camm is not appearing in the registration on the official website of Andhra Pradesh Medical Council at registration number 153427, due to which the registration of Dr. Narendra John Camm seems suspicious at first sight, and also, without registration in Madhya Pradesh Medical Council, no doctor can provide his services in Madhya Pradesh as per the rules..." the FIR further said.

"'The doctor did surgery (angioplasty) on 15 heart patients in January-February 2025. Out of these, seven patients died. Some relatives contacted us after which I complained to CMHO MK Jain in February. But no action was taken by CMHO so I, along with the victims' families, filed a complaint to the National Human Rights Commission in March," said Damoh child welfare committee chairman Deepak Tiwari.

The hospital in-charge Pushpa Khare told the CMHO that the doctor was hired through an agency. "The fraud was committed with us as well. We are supporting the administration in the investigation... He joined on January 1 and left in February without informing anyone," she said.

Meanwhile, Pradeep Shukla, the son of former Chhattisgarh assembly speaker Rajendra Prasad Shukla has alleged that the accused performed surgery on his father at a private hospital in Bilaspur in 2006, following which the latter died. "Yadav suggested and performed heart surgery on my father and then he was kept on a ventilator for nearly 18 days before he was declared dead on August 20, 2006," Pradeep was quoted as saying by PTI.

RAJASTHAN PATRIKA, Jabalpur, 9.4.2025
Page No. 3, Size:(12.12)cms X (13.26)cms.

कोर्ट से निकलते ही आरोपी पर फूटा वकीलों का गुस्सा, 5 दिन रिमांड पर नरेंद्र

दमोह में मौत बांटने वाले डॉक्टर ने माना-हां मैंने बनाए फर्जी दस्तावेज

आरोपी नरेंद्र कहानियों में बड़े पेच...

1. मेरे पास कार्डियोलॉजी की डिग्री.. इस पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के जाली हस्ताक्षर
2. मेरे पास मेडिकल की डिग्री... यात्रा के दौरान खो गई, जो दिखाई उस पर न रोल नंबर, न रजिस्ट्रेशन
3. मेरे सीने में दर्द... पुलिस ने कराई ईसीजी, गड़बड़ी जैसा कुछ भी नहीं

मानवाधिकार आयोग ने जुटाए 5000 पेज के दस्तावेज, आज दिल्ली लौटेगी टीम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दमोह. लंदन का डॉक्टर बन मिशन अस्पताल में मरीजों के दिल की सर्जरी कर मौत बांटने वाले नरेंद्र यादव को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया। जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद पुलिस कोर्ट ले गई। उसे देख वकील भड़क गए और पीटने की कोशिश की, पुलिस ने बमुश्किल बचाया। पुलिस पूछताछ में नरेंद्र ने कहा, हां! नाम बदलने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए। मेरे पास मेडिकल की डिग्रियां हैं, पर यात्रा में गुम हो गई। सीएमएचओ डॉ. मुकेश जैन की जांच में डिग्री फर्जी निकली। कार्डियोलॉजी की डिग्री पर पुद्दुचेरी विवि के चांसलर के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दस्तखत मिले। हस्ताक्षर का मिलान करने पर प्रथम दृष्ट्या अंसारी के दस्तखत भी फर्जी मिले। इस पर रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर भी नहीं थे। इससे पहले सोमवार को गिरफ्त में आए नरेंद्र ने पुलिस से सीने में दर्द की शिकायत की। पुलिस ने ईसीजी कराई। अविभाजित मप्र के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की मौत के बाद मामले में बेटे प्रो. प्रदीप शुक्ल की शिकायत पर बिलासपुर सीएमएचओ ने अपोलो हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है।

दमोह कोर्ट से रिमांड पर लेने के बाद आरोपी नरेंद्र को ले जाती पुलिस।

आरोपी को देख इतना गुस्सा भड़का कि पुलिस की गाड़ी का दरवाजा टूट गया।

जबलपुर मेडिकल कॉलेज करेगा डिग्री की जांच, एसपी की विशेष टीम जाएगी सिलीगुड़ी

आरोपी नरेंद्र कानपुर का रहने वाला है। उसकी पत्नी अनिता रावत हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम देखती है। एसपी ने बताया, आरोपी की उसके बताए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री की जांच होगी। इसके टीम बनाई है। टीम सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और कोलकाता में संबंधित मेडिकल कॉलेज में पड़ताल करेगी।

इधर, डिग्री की जांच को जबलपुर मेडिकल कॉलेज की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम मिशन अस्पताल के कैथलैब की भी जांच करेगी। सप्ताहभर में रिपोर्ट देगी।

पीड़ित बेटी बोली- पिता को दिए 5 इंजेक्शन, मौत

मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच पूरी हो गई। टीम ने 5 हजार पेज के दस्तावेज जुटाए। बुधवार को टीम दिल्ली लौटेगी। टीम ने 2 पीड़ितों के बयान लिए। रिटायर्ड टीआइ इस्माइल खान की बेटी रेहाना ने इलाज संबंधी रिकॉर्ड दिए। बोली-नरेंद्र ने 5 इंजेक्शन लगाए। हालत बिगड़ी, पिता की मौत हो गई। दसौंदा रैकवार ने भी यही शिकायत की।

रौब ऐसा...गनर लेकर चलता था डॉक्टर

जांच में पता चला, आरोपी नरेंद्र बेहद शातिर है। अस्पताल में डॉक्टरों को संदेह न हो, इसलिए वह खुद को अलग दिखाता था। एक गनर साथ रखता था। बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बता बड़े होटल में ठहरता था। यह सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। फरटिदार अंग्रेजी से लोगों को प्रभावित करता था, इससे शक नहीं होता था। खास यह है कि वह महिला मरीजों को ही डील करता था। 8 मरीजों में जिंदा बचे एक मरीज के परिजन ने संदेह जताया तो डॉक्टर ने मरीज को जबलपुर रेफर किया था।

RAJASTHAN PATRIKA, Bhopal, 9.4.2025
Page No. 3, Size:(12.12)cms X (13.26)cms.

कोर्ट से निकलते ही आरोपी पर फूटा वकीलों का गुस्सा, 5 दिन रिमांड पर नरेंद्र

दमोह में मौत बांटने वाले डॉक्टर ने माना-हां मैंने बनाए फर्जी दस्तावेज

आरोपी नरेंद्र कहानियों में बड़े पेच...

1. मेरे पास कार्डियोलॉजी की डिग्री.. इस पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के जाली हस्ताक्षर
2. मेरे पास मेडिकल की डिग्री... यात्रा के दौरान खो गई, जो दिखाई उस पर न रोल नंबर, न रजिस्ट्रेशन
3. मेरे सीने में दर्द... पुलिस ने कराई ईसीजी, गड़बड़ी जैसा कुछ भी नहीं

मानवाधिकार आयोग ने जुटाए 5000 पेज के दस्तावेज, आज दिल्ली लौटेगी टीम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दमोह. लंदन का डॉक्टर बन मिशन अस्पताल में मरीजों के दिल की सर्जरी कर मौत बांटने वाले नरेंद्र यादव को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया। जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद पुलिस कोर्ट ले गई। उसे देख वकील भड़क गए और पीटने की कोशिश की, पुलिस ने बमुश्किल बचाया। पुलिस पूछताछ में नरेंद्र ने कहा, हां! नाम बदलने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए। मेरे पास मेडिकल की डिग्रियां हैं, पर यात्रा में गुम हो गई। सीएमएचओ डॉ. मुकेश जैन की जांच में डिग्री फर्जी निकली। कार्डियोलॉजी की डिग्री पर पुद्दुचेरी विवि के चांसलर के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दस्तखत मिले। हस्ताक्षर का मिलान करने पर प्रथम दृष्ट्या अंसारी के दस्तखत भी फर्जी मिले। इस पर रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर भी नहीं थे। इससे पहले सोमवार को गिरफ्त में आए नरेंद्र ने पुलिस से सीने में दर्द की शिकायत की। पुलिस ने ईसीजी कराई। अविभाजित मप्र के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की मौत के बाद मामले में बेटे प्रो. प्रदीप शुक्ल की शिकायत पर बिलासपुर सीएमएचओ ने अपोलो हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है।

दमोह कोर्ट से रिमांड पर लेने के बाद आरोपी नरेंद्र को ले जाती पुलिस।

आरोपी को देख इतना गुस्सा भड़का कि पुलिस की गाड़ी का दरवाजा टूट गया।

जबलपुर मेडिकल कॉलेज करेगा डिग्री की जांच, एसपी की विशेष टीम जाएगी सिलीगुड़ी

आरोपी नरेंद्र कानपुर का रहने वाला है। उसकी पत्नी अनिता रावत हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम देखती है। एसपी ने बताया, आरोपी की उसके बताए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री की जांच होगी। इसके टीम बनाई है। टीम सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और कोलकाता में संबंधित मेडिकल कॉलेज में पड़ताल करेगी।

इधर, डिग्री की जांच को जबलपुर मेडिकल कॉलेज की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम मिशन अस्पताल के कैथलैब की भी जांच करेगी। सप्ताहभर में रिपोर्ट देगी।

पीड़ित बेटी बोली- पिता को दिए 5 इंजेक्शन, मौत

मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच पूरी हो गई। टीम ने 5 हजार पेज के दस्तावेज जुटाए। बुधवार को टीम दिल्ली लौटेगी। टीम ने 2 पीड़ितों के बयान लिए। रिटायर्ड टीआइ इस्माइल खान की बेटी रेहाना ने इलाज संबंधी रिकॉर्ड दिए। बोली-नरेंद्र ने 5 इंजेक्शन लगाए। हालत बिगड़ी, पिता की मौत हो गई। दसौंदा रैकवार ने भी यही शिकायत की।

रौब ऐसा...गनर लेकर चलता था डॉक्टर

जांच में पता चला, आरोपी नरेंद्र बेहद शातिर है। अस्पताल में डॉक्टरों को संदेह न हो, इसलिए वह खुद को अलग दिखाता था। एक गनर साथ रखता था। बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बता बड़े होटल में ठहरता था। यह सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। फरटिदार अंग्रेजी से लोगों को प्रभावित करता था, इससे शक नहीं होता था। खास यह है कि वह महिला मरीजों को ही डील करता था। 8 मरीजों में जिंदा बचे एक मरीज के परिजन ने संदेह जताया तो डॉक्टर ने मरीज को जबलपुर रेफर किया था।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

RAJASTHAN PATRIKA, Gwalior, 9.4.2025
Page No. 3, Size:(12.12)cms X (13.26)cms.

कोर्ट से निकलते ही आरोपी पर फूटा वकीलों का गुस्सा, 5 दिन रिमांड पर नरेंद्र

दमोह में मौत बांटने वाले डॉक्टर ने माना-हां मैंने बनाए फर्जी दस्तावेज

आरोपी नरेंद्र कहानियों में बड़े पेंच...

1. मेरे पास कार्डियोलॉजी की डिग्री.. इस पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के जाली हस्ताक्षर
2. मेरे पास मेडिकल की डिग्री... यात्रा के दौरान खो गई, जो दिखाई उस पर न रोल नंबर, न रजिस्ट्रेशन
3. मेरे सीने में दर्द... पुलिस ने कराई ईसीजी, गड़बड़ी जैसा कुछ भी नहीं

मानवाधिकार आयोग ने जुटाए 5000 पेज के दस्तावेज, आज दिल्ली लौटेगी टीम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दमोह. लंदन का डॉक्टर बन मिशन अस्पताल में मरीजों के दिल की सर्जरी कर मौत बांटने वाले नरेंद्र यादव को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया। जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद पुलिस कोर्ट ले गई। उसे देख वकील भड़क गए और पीटने की कोशिश की, पुलिस ने बमुश्किल बचाया। पुलिस पूछताछ में नरेंद्र ने कहा, हां! नाम बदलने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए। मेरे पास मेडिकल की डिग्रियां हैं, पर यात्रा में गुम हो गई। सीएमएचओ डॉ. मुकेश जैन की जांच में डिग्री फर्जी निकली। कार्डियोलॉजी की डिग्री पर पुद्दुचेरी विवि के चांसलर के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दस्तखत मिले। हस्ताक्षर का मिलान करने पर प्रथम दृष्ट्या अंसारी के दस्तखत भी फर्जी मिले। इस पर रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर भी नहीं थे। इससे पहले सोमवार को गिरफ्त में आए नरेंद्र ने पुलिस से सीने में दर्द की शिकायत की। पुलिस ने ईसीजी कराई। अविभाजित मप्र के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की मौत के बाद मामले में बेटे प्रो. प्रदीप शुक्ल की शिकायत पर बिलासपुर सीएमएचओ ने अपोलो हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है।

दमोह कोर्ट से रिमांड पर लेने के बाद आरोपी नरेंद्र को ले जाती पुलिस।

आरोपी को देख इतना गुस्सा भड़का कि पुलिस की गाड़ी का दरवाजा टूट गया।

जबलपुर मेडिकल कॉलेज करेगा डिग्री की जांच, एसपी की विशेष टीम जाएगी सिलीगुड़ी

आरोपी नरेंद्र कानपुर का रहने वाला है। उसकी पत्नी अनिता रावत हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम देखती है। एसपी ने बताया, आरोपी की उसके बताए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री की जांच होगी। इसके टीम बनाई है। टीम सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और कोलकाता में संबंधित मेडिकल कॉलेज में पड़ताल करेगी।

इधर, डिग्री की जांच को जबलपुर मेडिकल कॉलेज की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम मिशन अस्पताल के कैथलैब की भी जांच करेगी। सप्ताहभर में रिपोर्ट देगी।

पीड़ित बेटी बोली- पिता को दिए 5 इंजेक्शन, मौत

मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच पूरी हो गई। टीम ने 5 हजार पेज के दस्तावेज जुटाए। बुधवार को टीम दिल्ली लौटेगी। टीम ने 2 पीड़ितों के बयान लिए। रिटायर्ड टीआइ इस्माइल खान की बेटी रेहाना ने इलाज संबंधी रिकॉर्ड दिए। बोली-नरेंद्र ने 5 इंजेक्शन लगाए। हालत बिगड़ी, पिता की मौत हो गई। दसौदा रैकवार ने भी यही शिकायत की।

रौब ऐसा...गनर लेकर चलता था डॉक्टर

जांच में पता चला, आरोपी नरेंद्र बेहद शातिर है। अस्पताल में डॉक्टरों को संदेह न हो, इसलिए वह खुद को अलग दिखाता था। एक गनर साथ रखता था। बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बता बड़े होटल में ठहरता था। यह सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। फरटिदार अंग्रेजी से लोगों को प्रभावित करता था, इससे शक नहीं होता था। खास यह है कि वह महिला मरीजों को ही डील करता था। 8 मरीजों में जिंदा बचे एक मरीज के परिजन ने संदेह जताया तो डॉक्टर ने मरीज को जबलपुर रेफर किया था।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

RAJASTHAN PATRIKA, Indore, 9.4.2025
Page No. 3, Size:(12.12)cms X (13.26)cms.

कोर्ट से निकलते ही आरोपी पर फूटा वकीलों का गुस्सा, 5 दिन रिमांड पर नरेंद्र

दमोह में मौत बांटने वाले डॉक्टर ने माना-हां मैंने बनाए फर्जी दस्तावेज

आरोपी नरेंद्र की कहानियों में बड़े पेच...

1. मेरे पास कार्डियोलॉजी की डिग्री.. इस पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के जाली हस्ताक्षर
2. मेरे पास मेडिकल की डिग्री... यात्रा के दौरान खो गई, जो दिखाई उस पर न रोल नंबर, न रजिस्ट्रेशन
3. मेरे सीने में दर्द... पुलिस ने कराई ईसीजी, गड़बड़ी जैसा कुछ भी नहीं

मानवाधिकार आयोग ने जुटाए 5000 पेज के दस्तावेज, आज दिल्ली लौटेगी टीम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

दमोह. लंदन का डॉक्टर बन मिशन अस्पताल में मरीजों के दिल की सर्जरी कर मौत बांटने वाले नरेंद्र यादव को पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पर लिया। जिला अस्पताल में मेडिकल के बाद पुलिस कोर्ट ले गई। उसे देख वकील भड़क गए और पीटने की कोशिश की, पुलिस ने बमुश्किल बचाया। पुलिस पूछताछ में नरेंद्र ने कहा, हां! नाम बदलने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए। मेरे पास मेडिकल की डिग्रियां हैं, पर यात्रा में गुम हो गई। सीएमएचओ डॉ. मुकेश जैन की जांच में डिग्री फर्जी निकली। कार्डियोलॉजी की डिग्री पर पुद्दुचेरी विवि के चांसलर के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दस्तखत मिले। हस्ताक्षर का मिलान करने पर प्रथम दृष्ट्या अंसारी के दस्तखत भी फर्जी मिले। इस पर रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर भी नहीं थे। इससे पहले सोमवार को गिरफ्त में आए नरेंद्र ने पुलिस से सीने में दर्द की शिकायत की। पुलिस ने ईसीजी कराई। अविभाजित मप्र के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ल की मौत के बाद मामले में बेटे प्रो. प्रदीप शुक्ल की शिकायत पर बिलासपुर सीएमएचओ ने अपोलो हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है।

दमोह कोर्ट से रिमांड पर लेने के बाद आरोपी नरेंद्र को ले जाती पुलिस।

आरोपी को देख इतना गुस्सा भड़का कि पुलिस की गाड़ी का दरवाजा टूट गया।

जबलपुर मेडिकल कॉलेज करेगा डिग्री की जांच, एसपी की विशेष टीम जाएगी सिलीगुड़ी

आरोपी नरेंद्र कानपुर का रहने वाला है। उसकी पत्नी अनिता रावत हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम देखती है। एसपी ने बताया, आरोपी की उसके बताए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री की जांच होगी। इसके टीम बनाई है। टीम सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और कोलकाता में संबंधित मेडिकल कॉलेज में पड़ताल करेगी।

इधर, डिग्री की जांच को जबलपुर मेडिकल कॉलेज की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। टीम मिशन अस्पताल के कैथलैब की भी जांच करेगी। सप्ताहभर में रिपोर्ट देगी।

पीड़ित बेटी बोली- पिता को दिए 5 इंजेक्शन, मौत

मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच पूरी हो गई। टीम ने 5 हजार पेज के दस्तावेज जुटाए। बुधवार को टीम दिल्ली लौटेगी। टीम ने 2 पीड़ितों के बयान लिए। रिटायर्ड टीआइ इस्माइल खान की बेटी रेहाना ने इलाज संबंधी रिकॉर्ड दिए। बोली-नरेंद्र ने 5 इंजेक्शन लगाए। हालत बिगड़ी, पिता की मौत हो गई। दसौदा रैकवार ने भी यही शिकायत की।

रौब ऐसा...गनर लेकर चलता था डॉक्टर

जांच में पता चला, आरोपी नरेंद्र बेहद शातिर है। अस्पताल में डॉक्टरों को संदेह न हो, इसलिए वह खुद को अलग दिखाता था। एक गनर साथ रखता था। बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट बता बड़े होटल में ठहरता था। यह सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। फरटिदार अंग्रेजी से लोगों को प्रभावित करता था, इससे शक नहीं होता था। खास यह है कि वह महिला मरीजों को ही डील करता था। 8 मरीजों में जिंदा बचे एक मरीज के परिजन ने संदेह जताया तो डॉक्टर ने मरीज को जबलपुर रेफर किया था।

PIB

एनएचआरसी, भारत ने देश भर की विभिन्न जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों सहित सभी कैदियों की कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई

रिपोर्ट में महिला कैदियों और शिशुओं के साथ रहने वाली महिलाओं, दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों, साथ ही एक वर्ष से अधिक समय से जेलों में बंद विचाराधीन महिला और पुरुष कैदियों की संख्या शामिल होनी चाहिए

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2120117

Posted On: 08 APR 2025 5:21PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने देश भर की जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों सहित सभी कैदियों की विभिन्न कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया है। इनमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना, आधारभूत सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है। देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट के साथ-साथ शिकायतों के माध्यम से इसके विशेष मॉनिटर और रिपोर्टर द्वारा इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है। महिला कैदियों की गरिमा और सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक कष्ट, पर्याप्त शौचालय, सैनिटरी नैपकिन, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के बिना अस्वास्थ्यकर स्थिति, खराब गुणवत्ता वाला भोजन जिसके कारण विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, जेलों में उनके साथ रहने वाली महिला कैदियों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहित उनके कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न होना अन्य चिंताओं में शामिल हैं।

इसलिए, आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निम्नलिखित पर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है:

i.) अपने राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या,

ii.) उन महिला कैदियों की संख्या जिनके बच्चे माताओं के जेल में रहने के कारण जेलों में बंद हैं;

iii.) महिला कैदियों की संख्या, जो दोषी करार दी गई हैं और जो विचाराधीन कैदी हैं;

iv.) जेल में एक वर्ष से अधिक समय से बंद विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या;

v.) विचाराधीन पुरुष कैदियों की संख्या तथा एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद कैदियों की संख्या।

***

एमजी/केसी/एसकेएस/एसवी (Release ID: 2120117) Visitor Counter : 85

The Hindu

NHRC notice to States on difficulties faced by prisoners

Human Rights Commission took suo motu cognisance of the poor conditions in jails, especially for women inmates and their children

https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-notice-to-states-on-difficulties-faced-by-prisoners/article69427432.ece

Updated - April 08, 2025 08:28 pm IST - New Delhi:

Ishita Mishra

Taking suo motu cognisance of various difficulties being faced by prisoners, including women inmates and their children in jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued notice to the Chief Secretaries of all the States and union territories seeking replies on the issue.

The issues have been brought to the NHRC notice by its Special Monitors and Rapporteurs through their reports after visiting various jails, as well as the complaints. The commission says it is concerned over the lack of basic amenities and healthcare facilities in jails along with overcrowding in prisons.

The Union government's response in the Lok Sabha in December last year stated that the latest published report on prisons in India compiled by the National Crime Records Bureau (NCRB) as of the year 2022 says that against the total available capacity of 4,36,266 inmates, 5,73,220 prisoners were lodged in the jails of the country.

"Some of the other concerns raised in the report include violation of the rights to dignity and safety of the women prisoners, increased violence against them, causing mental distress, unhygienic conditions without adequate toilets, sanitary napkins, clean drinking water facilities, poor quality food, resulting in malnourishment, particularly among pregnant women and lactating mothers, lack of educational opportunities to the children of women prisoners living in jails with them, non-implementation of welfare programmes, including legal aid, vocational training and rehabilitation," the commission said in its notice.

States have been asked to submit a detailed report within four weeks which should include the details of the number of women prisoners and their babies lodged in jails.

The NHRC has also asked for a segregate data on women and male undertrials languishing for more than a year in jails.

Hindustan Times

NHRC issues notices to states, UTs: seeks reports over issues faced by prisoners

https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-issues-notices-to-states-uts-seeks-reports-over-issues-faced-by-prisoners-101744118557641.html

PTI | Apr 08, 2025 06:52 PM IST

NHRC issues notices to states, UTs; seeks reports over issues faced by prisoners

New Delhi, Taking suo motu cognisance of difficulties being faced by prisoners including women inmates in various jails across the country, the National Human Rights Commission has issued notices to chief secretaries of all the states and Union Territories, seeking reports within four weeks.

NHRC issues notices to states, UTs; seeks reports over issues faced by prisoners

These problems include overcrowding, lack of basic amenities and healthcare facilities in jails, the NHRC said in a statement.

"The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails across the country, as well as the complaints," it said.

The Commission said it has issued notices to the chief secretaries of all the states and Union Territories seeking a report from them in four weeks, which should include various details.

These include the number of women prisoners lodged in jails in a state, the number of women prisoners whose babies are lodged in jails on account of the mothers being incarcerated, the number of women prisoners who are convicted prisoners and those who are undertrial prisoners, number of women undertrial prisoners who are languishing for more than a year in jail, and number of male undertrial prisoners and those who are languishing in jail for more than a year, the statement said.

Some of the other concerns raised include the violation of the rights to dignity and safety of the women prisoners, increased violence against them causing mental distress, unhygienic conditions without adequate toilets, sanitary napkins and clean drinking water facilities, it said.

Also, other concerns include poor quality food resulting in malnourishment, particularly in the case of pregnant women and lactating mothers, lack of educational opportunities for the children of women prisoners living in jails with them, non-implementation of their welfare programmes including legal aid, vocational training and rehabilitation, the statement said.

Deccan Chronicle

NHRC issues notices to CS of all States, UTs calling for reports in four weeks

https://www.deccanchronicle.com/southern-states/telangana/nhrc-issues-notices-to-cs-of-all-states-uts-calling-for-reports-in-four-weeks-1871777

M Srinivas 8 April 2025 6:20 PM

NHRC takes suo motu cognisance of difficulties being faced by prisoners

Hyderabad: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the various difficulties being faced by the prisoners, including the women inmates and their children, in jails across the country. These include overcrowding, lack of basic amenities and healthcare facilities in jails. The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails across the country, as well as the complaints.

Some other concerns raised include the violation of the rights to dignity and safety of the women prisoners, increased violence against them causing mental distress, unhygienic conditions without adequate toilet, sanitary napkins, clean drinking water facilities, poor quality food resulting in malnourishment particularly in the pregnant women and lactating mothers. Lack of educational opportunities to children of women prisoners living in jails with them, non-implementation of their welfare programmes including legal aid, vocational training and rehabilitation were also raised.

Therefore, the Commission has issued notices to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories (UTs) to submit a report within four weeks on the following matters - the number of women prisoners lodged in jails in their State, number of women prisoners whose babies are lodged in jails on account of the mothers being incarcerated, the number of women prisoners, who are convicted prisoners and those who are undertrial prisoners. Details of the number of women undertrial prisoners who are languishing for more than a year in jail and the number of male undertrial prisoners and those who are languishing in jail for more than a year were also sought.

(Source : Deccan Chronicle)

LatestLY

India News | NHRC Issues Notices to States, UTs: Seeks Reports over Issues Faced by Prisoners

Get latest articles and stories on India at LatestLY. Taking suo motu cognisance of difficulties being faced by prisoners including women inmates in various jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to chief secretaries of all the states and Union Territories, seeking reports within four weeks.

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-issues-notices-to-states-uts-seeks-reports-over-issues-faced-by-prisoners-6767892.html

Agency News PTI | Apr 08, 2025 06:50 PM IST

New Delhi, Apr 8 (PTI) Taking suo motu cognisance of difficulties being faced by prisoners including women inmates in various jails across the country, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to chief secretaries of all the states and Union Territories, seeking reports within four weeks.

These problems include overcrowding, lack of basic amenities and healthcare facilities in jails, the NHRC said in a statement. "The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails across the country, as well as the complaints," it said.

The Commission said it has issued notices to the chief secretaries of all the states and Union Territories (UTs) seeking a report from them in four weeks, which should include various details.

These include the number of women prisoners lodged in jails in a state, the number of women prisoners whose babies are lodged in jails on account of the mothers being incarcerated, the number of women prisoners who are convicted prisoners and those who are undertrial prisoners, number of women undertrial prisoners who are languishing for more than a year in jail, and number of male undertrial prisoners and those who are languishing in jail for more than a year, the statement said. Some of the other concerns raised include the violation of the rights to dignity and safety of the women prisoners, increased violence against them causing mental distress, unhygienic conditions without adequate toilets, sanitary napkins and clean drinking water facilities, it said.

Also, other concerns include poor quality food resulting in malnourishment, particularly in the case of pregnant women and lactating mothers, lack of educational opportunities for the children of women prisoners living in jails with them, non-implementation of their welfare programmes including legal aid, vocational training and rehabilitation, the statement said.

(This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News feed, LatestLY Staff may not have modified or edited the content body)

Prameyanews

NHRC seeks reports from Chief Secretaries on status of jails

https://www.prameyanews.com/nhrc-seeks-reports-from-chief-secretaries-on-status-of-jails

Published By : Prasanta Dash | April 8, 2025 7:03 PM

New Delhi, April 8: The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognisance of the various difficulties being faced by the prisoners, including the women inmates and their children, in the jails across the country. These include overcrowding, a lack of basic amenities and healthcare facilities in jails. The issues have been brought to its notice by its Special Monitors and Rapporteurs, through their reports after visiting various jails across the country, as well as the complaints.

Some of the other concerns raised include the violation of the rights to dignity and safety of the women prisoners, increased violence against them causing mental distress, unhygienic conditions without adequate toilet, sanitary napkins, clean drinking water facilities, poor quality food resulting in malnourishment particularly in the pregnant women and lactating mothers, lack of educational opportunities to the children of women prisoners living in jails with them, non-implementation of their welfare programmes including legal aid, vocational training and rehabilitation.

Therefore, the Commission has issued notices to the Chief Secretaries of all the states and Union Territories to submit their reports within four-week time.

Prabhat Khabar

NHRC: जेलों में बंद महिला कैदियों की मौजूदा स्थिति पर मानवाधिकार आयोग ने राज्यों से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेल में एक वर्ष से अधिक समय से बंद विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या, विचाराधीन पुरुष कैदियों की संख्या तथा एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद कैदियों की संख्या की विस्तृत जानकारी 4 हफ्ते में देने का निर्देश दिया है. इस बाबत सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है.

https://www.prabhatkhabar.com/national/nhrc-report-from-states-of-women-prisoners/

By Vinay Tiwari | April 8, 2025 7:02 PM

NHRC: देश भर की जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों सहित सभी कैदियों की विभिन्न कठिनाइयों को लेकर हाल में कई खबरें सामने आयी है. जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होना, आधारभूत सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मामला भी सामने आया है. इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) स्वतः संज्ञान लिया है.

आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी कर अपने राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या, उन महिला कैदियों की संख्या जिनके बच्चे माताओं के जेल में रहने के कारण जेलों में बंद हैं, महिला कैदियों की संख्या, जो दोषी करार दी गई हैं और जो विचाराधीन कैदी हैं, जेल में एक वर्ष से अधिक समय से बंद विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या, विचाराधीन पुरुष कैदियों की संख्या तथा एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद कैदियों की संख्या की विस्तृत जानकारी 4 हफ्ते में देने का निर्देश दिया है.

मूलभूत सुविधाओं की कमी चिंता का विषय

आयोग का कहना है कि महिला कैदियों की गरिमा और सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक कष्ट, पर्याप्त शौचालय, सैनिटरी नैपकिन, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के बिना अस्वास्थ्यकर स्थिति, खराब गुणवत्ता वाला भोजन जिसके कारण विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, जेलों में उनके साथ रहने वाली महिला कैदियों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहित उनके कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन न होना गंभीर चिंता का विषय है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 की शुरुआत तक 134799 लोग सुनवाई के इंतजार में जेल में बंद थे, जिनमें से 11448 पांच साल से अधिक समय से बिना सजा के जेल में हैं. गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है. केंद्र सरकार ने तय समय से अधिक जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की योजना पर काम कर रही है.

Ommcom

NHRC Takes Suo Motu Cognisance Of Prisoners' Plight, Issues Notices To States And UTs

https://ommcomnews.com/india-news/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-prisoners-plight-issues-notices-to-states-and-uts/

by OMMCOM NEWS | April 8, 2025 in Nation

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the grave issues faced by prisoners, particularly women inmates and their children, in jails across the country. In a significant move to address the systemic challenges in the prison system, the NHRC has issued notices to the Chief Secretaries of all States and Union Territories, calling for comprehensive reports on the situation within four weeks.

The NHRC's intervention comes in response to numerous reports and complaints raised by its Special Monitors and Rapporteurs after their visits to various jails across India. The reports highlighted several pressing issues, including overcrowding, a lack of basic amenities, and inadequate healthcare facilities in prisons. These issues are compounded for women prisoners, who face unique challenges regarding safety, dignity, and health.

Therefore, the Commission has issued notices to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories to submit a report within four weeks on the following:

NHRC has been informed that many jails across the country are plagued with overcrowding, leaving prisoners, especially women and children, without access to proper sanitation, clean drinking water, and adequate food. Women prisoners, in particular, suffer from a lack of sanitary products, hygienic conditions, and basic necessities.

Reports from NHRC Special Monitors revealed increasing violence against women prisoners, leading to mental distress and harm to their dignity. The lack of effective safeguards has put these inmates at risk.

The quality of food provided in jails has been cited as inadequate, resulting in malnutrition, especially among pregnant women and lactating mothers. The absence of proper healthcare facilities exacerbates these conditions.

Women prisoners who live with their children in jail face a severe lack of educational opportunities for their children. The welfare programmes, including access to education and legal aid, have been poorly implemented, leaving children without the means to receive basic schooling.

There have been concerns about the non-implementation of essential programmes aimed at the welfare of prisoners. These include vocational training, legal aid, and rehabilitation efforts that could help prisoners reintegrate into society.

In its notice, the NHRC has requested that the Chief Secretaries of all States and Union Territories submit a detailed report addressing the following points within four weeks:

The number of women prisoners lodged in Jails in their State

The number of women prisoners whose babies are lodged in jails on account of the mothers being incarcerated

The number of women prisoners, who are convicted prisoners and those who are undertrial prisoners

The number of women undertrial prisoners who are languishing for more than a year in jail

The number of male undertrial prisoners and those who are languishing in jail for more than a year.

(IANS)

Dainik Bhaskar

शिक्षा: एनएचआरसी ने महिला कैदियों की सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा पर राज्यों से मांगी रिपोर्ट

https://www.bhaskarhindi.com/other/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-prisoners-plight-issues-notices-to-states-and-uts-1129751

8 April 2025 8:37 PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा है कि देश की विभिन्न जेलों में मौजूद बच्चों के लिए शिक्षा के क्या अवसर उपलब्ध हैं। उनके शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी पर क्या किया जा रहा है। इसके बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया गया है।

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा है कि देश की विभिन्न जेलों में मौजूद बच्चों के लिए शिक्षा के क्या अवसर उपलब्ध हैं। उनके शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी पर क्या किया जा रहा है। इसके बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया गया है।

देश भर की विभिन्न जेलों में महिला कैदियों, उनके साथ रह रहे उनके बच्चों और अन्य कैदियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के मामले पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अगले चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट देनी होगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश भर की जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों सहित सभी कैदियों की विभिन्न कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने महिला कैदियों की सुरक्षा, हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, शौचालय, खराब भोजन जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर संज्ञान लिया है। जो विषय एनएचआरसी के समक्ष हैं, उनमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना, आधारभूत सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है।

देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट के साथ-साथ शिकायतों के माध्यम से इसके विशेष मॉनिटर और रिपोर्टर द्वारा इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है।

एनएचआरसी के मुताबिक, कई विषय सामने आए हैं जिनमें महिला कैदियों की गरिमा और सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक कष्ट, पर्याप्त शौचालय, सैनिटरी नैपकिन, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के बिना अस्वास्थ्यकर स्थिति, खराब गुणवत्ता वाला भोजन आदि शामिल हैं।

खराब गुणवत्ता वाले भोजन के कारण विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण आ रहा है। इसके अलावा, आयोग के मुताबिक जेलों में महिला कैदियों के साथ रहने वाले उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी, कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न होना भी चिंता के विषय हैं। अब आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है कि मुख्य सचिव अपने राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या बताएं। उन महिला कैदियों की संख्या बताएं जिनके बच्चे माताओं के जेल में रहने के कारण जेलों में रह रहे हैं। आयोग ने पूछा है कि दोषी करार दी गई महिला कैदियों की संख्या और विचाराधीन कैदी कितनी हैं? जेल में एक वर्ष से अधिक समय से बंद विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या कितनी है? आयोग यह भी जानना चाहता है कि विचाराधीन पुरुष कैदियों की संख्या कितनी है तथा एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद कैदियों की संख्या कितनी है?

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

LatestLY

देश की खबरें | मानवाधिकार आयोग ने राज्यों को नोटिस जारी कर कैदियों की समस्याओं पर रिपोर्ट मांगी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश भर की विभिन्न जेलों में कैदियों को हो रही कठिनाइयों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

https://hindi.latestly.com/agency-news/the-human-rights-commission-issued-notice-to-the-states-seeking-a-report-on-the-problems-of-the-prisoners-r-2568782.html

एजेंसी न्यूज Bhasha | Apr 08, 2025 09:12 PM IST

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश भर की विभिन्न जेलों में कैदियों को हो रही कठिनाइयों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि इन समस्याओं में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है।

इसने कहा, “देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद तैयार रिपोर्ट और शिकायतों के माध्यम से इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है।”

बयान के मुताबिक, आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें विभिन्न विवरण शामिल होने चाहिए।

इसमें कहा गया कि रिपोर्ट में मांगे गए विवरण में राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या, उन महिला कैदियों की संख्या, जिनके बच्चे उनके साथ जेल में बंद हैं, उन महिला कैदियों की संख्या जो दोषी व विचाराधीन कैदी हैं, और एक साल से अधिक समय से जेल में बंद महिला विचाराधीन कैदियों तथा पुरुष विचाराधीन कैदियों का ब्योरा शामिल है।

बयान के मुताबिक, कुछ अन्य चिंताओं में महिला कैदियों के सम्मान व सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक तनाव, पर्याप्त शौचालयों, सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के बिना अस्वच्छ स्थितियां शामिल हैं।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

The Print

मानवाधिकार आयोग ने राज्यों को नोटिस जारी कर कैदियों की समस्याओं पर रिपोर्ट मांगी

https://hindi.theprint.in/india/human-rights-commission-issued-notice-to-the-states-and-sought-report-on-the-problems-of-prisoners/804346/

भाषा | 8 April, 2025 09:18 pm IST

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश भर की विभिन्न जेलों में कैदियों को हो रही कठिनाइयों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि इन समस्याओं में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है।

इसने कहा, “देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद तैयार रिपोर्ट और शिकायतों के माध्यम से इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है।”

बयान के मुताबिक, आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है, जिसमें विभिन्न विवरण शामिल होने चाहिए।

इसमें कहा गया कि रिपोर्ट में मांगे गए विवरण में राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या, उन महिला कैदियों की संख्या, जिनके बच्चे उनके साथ जेल में बंद हैं, उन महिला कैदियों की संख्या जो दोषी व विचाराधीन कैदी हैं, और एक साल से अधिक समय से जेल में बंद महिला विचाराधीन कैदियों तथा पुरुष विचाराधीन कैदियों का ब्योरा शामिल है।

बयान के मुताबिक, कुछ अन्य चिंताओं में महिला कैदियों के सम्मान व सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक तनाव, पर्याप्त शौचालयों, सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ पेयजल सुविधाओं के बिना अस्वच्छ स्थितियां शामिल हैं।

भाषा जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

Hindustan

कैदियों की समस्याओं पर एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस

https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-nhrc-directs-states-to-report-on-prisoners-issues-in-four-weeks-201744135849239.html

8 अप्रैल 2025

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेलों में कैदियों की समस्याओं पर नोटिस जारी किया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चार हफ्तों में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में कैदियों की संख्या,...

- मुख्य सचिवों को चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश नई दिल्ली, एजेंसी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देशभर के जेलों में कैदियों की समस्याओं पर स्वत: संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है।

आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने एक बयान में कहा कि इन समस्याओं में जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है।

इसने कहा, देशभर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद तैयार रिपोर्ट और शिकायतों के माध्यम से इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है। आयोग ने रिपोर्ट में मांगे गए विवरण में जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या, बच्चों के साथ महिला कैदियों की संख्या, दोषी व विचाराधीन महिला कैदी और एक साल से अधिक समय से जेल में बंद महिला विचाराधीन कैदियों तथा पुरुष विचाराधीन कैदियों का ब्योरा शामिल है।

Jagran

महिला कैदियों की कठिनाइयों पर NHRC ने जताई चिंता, राज्यों से पूछे कई कड़े सवाल

एनएचआरसी ने देशभर की विभिन्न जेलों में बंद महिला कैदियों और उनके बच्चों को हो रही कठिनाइयों पर स्वत संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मानीटर्स ने देशभर की विभिन्न जेलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव आदि का मुद्दा उठाया गया था।

https://www.jagran.com/news/national-nhrc-expressed-concern-over-the-difficulties-faced-by-women-prisoners-asked-many-tough-questions-to-the-states-23914607.html

By Jagran NewsEdited By: Piyush KumarUpdated: Tue, 08 Apr 2025 11:39 PM (IST)

HighLights

एनएचआरसी ने महिला कैदियों की कठनाइयों पर सभी राज्यों को जारी किया नोटिस

राज्यों को बताना होगा कि उनके यहां की जेलों में बंद महिला कैदियों की कितनी है संख्या

बताना होगा- कितनी महिला कैदी ऐसी हैं, जिनके बच्चे माताओं के साथ जेल में रह रहे हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देशभर की विभिन्न जेलों में बंद महिला कैदियों और उनके बच्चों को हो रही कठिनाइयों पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट भेजने को कहा है।

राज्यों को रिपोर्ट में महिला कैदियों और शिशुओं के साथ रहने वाली महिला कैदियों, दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों के साथ ही एक साल से ज्यादा समय से जेलों में बंद महिला और पुरुष विचाराधीन कैदियों की संख्या भी बतानी होगी।

आयोग ने महिला कैदियों की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मानीटर्स ने देशभर की विभिन्न जेलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव आदि का मुद्दा उठाया गया था। रिपोर्ट को देखकर आयोग ने महिला कैदियों की स्थिति पर स्वत: संज्ञान लिया है।

रिपोर्ट में महिला कैदियों के सम्मान और सुरक्षा के अधिकारों के उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक परेशानी, पर्याप्त शौचालय, सैनेटरी नैपकिन, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं का अभाव तथा खराब गुणवत्ता वाला भोजन का मुद्दा भी उठाया गया था।

रिपोर्ट में महिला कैदियों के साथ जेलों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के अवसरों की कमी, कानूनी सहायता, व्यवसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहित उनके कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्यवयन न होने का मुद्दा भी शामिल है। इसीलिए, आयोग ने रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है।

रिपोर्ट में राज्यों को इन सवालों का देना होगा जवाब

राज्यों को रिपोर्ट में बताना होगा कि उनके राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या क्या है। कितनी महिला कैदी ऐसी हैं जिनके बच्चे माताओं के साथ जेल में रह रहे हैं। कितनी महिला कैदी दोषी करार दी गई हैं और कितनी संख्या विचाराधीन महिला कैदियों की है। कितनी महिला कैदी ऐसी हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद हैं। पुरुष विचाराधीन कैदियों की संख्या कितनी है और कितने एक वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद हैं।

Times of India

HC stays NHRC proceedings in KIIT student suicide case

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/hc-stays-nhrc-proceedings-in-kiit-student-suicide-case/articleshow/120096615.cms

Lalmohan Patnaik / Apr 8, 2025, 17:59 IST

Cuttack: Orissa high court has issued a stay order on all National Human Rights Commission (NHRC) proceedings related to the alleged suicide of a Nepalese student at KIIT deemed to be University on Feb 16. The court has also suspended the NHRC's March 27 order that had held the university accountable for the incident, saying it had violated principles of natural justice as KIIT was not given an opportunity to be heard. Justice S K Panigrahi, while hearing a petition filed by KIIT and Kalinga Institute of Social Sciences (KISS), emphasized that adherence to principles of natural justice is crucial in quasi-judicial proceedings. The court has issued notice to NHRC to respond by April 26, with the next hearing scheduled for April 29.

"It must be underscored that when orders are passed by quasi-judicial authorities, adherence to the principles of natural justice is not a mere formality, but a foundational requirement. The absence of notice or the denial of an opportunity to be heard renders such exercise susceptible to challenge and vitiates the fairness of the process," the HC noted.

The case involves a complex series of events leading to the tragic death of a Nepalese student. According to university submissions, the deceased had initially filed a complaint against a fellow student on Jan 12, regarding inappropriate photographs. Despite attempted resolutions and written undertakings between parties, the situation escalated, ultimately leading to the student's death.

KIIT authorities challenged the NHRC's March 27 order in which it had criticized the university's handling of the situation, noting "gross negligence" by university officials and expressing concern over the mass exodus of students from hostels following the incident. KIIT authorities argued they were not provided with the inquiry report or findings before the order was issued, violating Section 16 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The court has directed various authorities, including the state govt, district collector (Khurda), police commissioner and UGC chairman to halt any actions based on the NHRC's order until the next hearing.

This case has gained national attention, with the Supreme Court including it in a broader examination of student suicides in educational institutions. A National Task Force, headed by former Supreme Court Judge S Ravindra Bhat has been formed to investigate such incidents across India.

Hindustan Times

Orissa HC stays NHRC actions against KIIT over Nepalese student's death

https://www.hindustantimes.com/india-news/orissa-hc-stays-nhrc-actions-against-kiit-over-nepalese-student-s-death-101744129973385.html

PTI | Apr 08, 2025 10:02 PM IST

Orissa HC stays NHRC actions against KIIT over Nepalese student's death

Cuttack, The Orissa High Court has stayed till the next date of hearing the proceedings of the National Human Rights Commission against the Kalinga Institute of Industrial Technology over a Nepalese student's death in February.

While hearing a petition by the KIIT, the single-judge bench of Justice Sanjeeb Kumar Panigrahi also ruled that no further actions could be taken against the private deemed to be university here till the court takes up the matter for further hearing on April 29.

The court also issued notices to all parties involved, including the NHRC, and directed them to submit their replies within three weeks.

The 20-year-old Nepalese woman's body was recovered from her hostel room inside the KIIT campus on February 16 following which tension mounted and students from the Himalayan nation were assaulted and forcibly evicted after they staged protests. The incident had raised a nationwide outrage and the prime minister of Nepal also intervened in the matter.

Finding gross negligence on the part of the KIIT authorities over the "suicide", the NHRC on March 27 sought an action taken report from the Odisha government, UGC and the National Assessment and Accreditation Council within four weeks.

In its petition, the KIIT argued that while the NHRC had taken suo motu cognisance of the student's death on March 3, it proceeded to issue directions on March 27 without notifying or seeking a response from the institution.

Bottom of Form

The KIIT submitted that this move violated the principles of natural justice, as the institute was not allowed to present its side.

The court, acknowledging the procedural lapse raised by the petitioner, in its order on Monday said that as an interim measure, directed that all further proceedings in the case, presently pending before the NHRC, shall remain stayed until the next date of listing of this matter.

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

LatestLY

India News | Orissa HC Stays NHRC Actions Against KIIT over Nepalese Student's Death

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The Orissa High Court has stayed till the next date of hearing the proceedings of the National Human Rights Commission (NHRC) against the Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) over a Nepalese student's death in February.

https://www.latestly.com/agency-news/india-news-orissa-hc-stays-nhrc-actions-against-kiit-over-nepalese-students-death-6768378.html

Agency News PTI | Apr 08, 2025 10:04 PM IST

Cuttack, Apr 8 (PTI) The Orissa High Court has stayed till the next date of hearing the proceedings of the National Human Rights Commission (NHRC) against the Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) over a Nepalese student's death in February.

While hearing a petition by the KIIT, the single-judge bench of Justice Sanjeeb Kumar Panigrahi also ruled that no further actions could be taken against the private deemed to be university here till the court takes up the matter for further hearing on April 29.

The court also issued notices to all parties involved, including the NHRC, and directed them to submit their replies within three weeks.

The 20-year-old Nepalese woman's body was recovered from her hostel room inside the KIIT campus on February 16 following which tension mounted and students from the Himalayan nation were assaulted and forcibly evicted after they staged protests. The incident had raised a nationwide outrage and the prime minister of Nepal also intervened in the matter.

Finding gross negligence on the part of the KIIT authorities over the “suicide”, the NHRC on March 27 sought an action taken report from the Odisha government, UGC and the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) within four weeks.

In its petition, the KIIT argued that while the NHRC had taken suo motu cognisance of the student's death on March 3, it proceeded to issue directions on March 27 without notifying or seeking a response from the institution. The KIIT submitted that this move violated the principles of natural justice, as the institute was not allowed to present its side.

The court, acknowledging the procedural lapse raised by the petitioner, in its order on Monday said that as an interim measure, directed that all further proceedings in the case, presently pending before the NHRC, shall remain stayed until the next date of listing of this matter.

(This is an unedited and auto-generated story from Syndicated News feed, LatestLY Staff may not have modified or edited the content body)

The New Indian Express

NHRC urged to lift Andhra HC stay on Chittoor encounter case

It also directed the AP government to pay Rs 5 lakh interim relief to kin of each victims and suggested a CBI probe into the incident.

https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2025/Apr/08/nhrc-urged-to-lift-andhra-hc-stay-on-chittoor-encounter-case

Express News Service | Updated on: 08 Apr 2025, 10:28 am

1 min read

MADURAI: The Joint Action Against Custodial Torture -Tamil Nadu & Puducherry (JAACTTN) has urged the National Human Rights Commission (NHRC) to take steps to get the interim stay of Andhra Pradesh High Court vacated so that the commission's directions regarding the Chittoor encounter killings can be implemented.

In a release issued on Monday to mark the 10th anniversary of the incident when 20 loggers from Tamil Nadu were shot dead in "self defence" by Andhra Pradesh Red Sanders Anti Smuggling Special Task Force (STF) in an encounter inside the Seshachalam forest in Chittoor district on April 7, 2015, JAACTTN legal advisor Henri Tiphange said due to the interim stay, proceedings on the writ petition has been pending.

In the aftermath of the incident, the NHRC gave a slew of directions including magisterial inquiry, safe custody of weapons used by the STF and the deceased, not tamper with evidence such as police register, log books till trial is completed.

It also directed the AP government to pay Rs 5 lakh interim relief to kin of each victims and suggested a CBI probe into the incident. The AP government filed a writ petition in the Andhra Pradesh High Court challenging the commission's directions and got a stay order.

Janta Se Rishta

NHRC से चित्तूर मुठभेड़ मामले पर आंध्र हाईकोर्ट की रोक हटाने का आग्रह

https://www.jantaserishta.com/local/tamil-nadu/nhrc-urged-to-lift-andhra-high-court-stay-on-chittoor-encounter-case-3941303

April 8, 2025

मदुरै: हिरासत में यातना के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई - तमिलनाडु और पुडुचेरी (जे.ए.ए.सी.टी.एन.) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) से आग्रह किया है कि वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम स्थगन को हटाने के लिए कदम उठाए, ताकि चित्तूर मुठभेड़ हत्याओं के संबंध में आयोग के निर्देशों को लागू किया जा सके।

7 अप्रैल, 2015 को चित्तूर जिले के शेषचलम जंगल के अंदर एक मुठभेड़ में आंध्र प्रदेश लाल चंदन तस्करी विरोधी विशेष कार्य बल (एस.टी.एफ.) द्वारा तमिलनाडु के 20 लकड़हारों को "आत्मरक्षा" में गोली मार दिए जाने की घटना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में, जे.ए.ए.सी.टी.एन. के कानूनी सलाहकार हेनरी टिफांगे ने कहा कि अंतरिम स्थगन के कारण रिट याचिका पर कार्यवाही लंबित है।

घटना के बाद एनएचआरसी ने कई निर्देश दिए, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच, एसटीएफ और मृतक द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों को सुरक्षित रखना, मुकदमा पूरा होने तक पुलिस रजिस्टर, लॉग बुक जैसे सबूतों से छेड़छाड़ न करना शामिल है।

इसने आंध्र प्रदेश सरकार को प्रत्येक पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपये की अंतरिम राहत देने का भी निर्देश दिया और घटना की सीबीआई जांच का सुझाव दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने आयोग के निर्देशों को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त किया।

Organiser

Tamil Nadu: NHRC seeks report from UGC, over alleged human rights violations in Chennai's Loyola College

https://organiser.org/2025/04/08/286441/bharat/tamil-nadu-nhrc-seeks-report-from-ugc-over-alleged-human-rights-violations-in-chennais-loyola-college/

April 8, 2025

In a major intervention, the National Human Rights Commission (NHRC) has issued formal notices to the University Grants Commission (UGC) and the Registrar of the University of Madras, demanding an Action Taken Report within four weeks regarding grave allegations of human rights violations and academic misconduct at Loyola College (Autonomous), Chennai. Additionally, a copy has been marked to the Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, to initiate appropriate administrative follow-up.

The action follows a detailed complaint filed by Legal Rights Protection Forum (LRPF), a Hyderabad-based legal advocacy group, which accused Loyola College of conducting its M.A. Philosophy program at an unauthorized off-campus Jesuit institute named Satya Nilayam, in blatant violation of University of Madras affiliation norms. The program, allegedly functioning without mandatory approvals, is claimed to be operating around 12 km away from the main Loyola campus, under a separate Jesuit-controlled entity.

More disturbingly, LRPF has alleged religious discrimination in student admissions to this program, with non-Christian students being systematically excluded, which, if true, constitutes a direct violation of Articles 15(1) and 29(2) of the Indian Constitution—guaranteeing equal access to public educational institutions irrespective of religion.

The complaint also points to a potential academic fraud, accusing Loyola College of misusing the name and official logo of the University of Madras to confer degrees that may lack legal and academic legitimacy due to improper affiliation. These allegations not only question the validity of degrees issued under such arrangements but also raise red flags about regulatory failure and institutional collusion.

Taking serious cognizance, the NHRC Bench led by Priyank Kanoongo invoked Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, classifying the issue as a possible grave human rights violation, warranting urgent institutional scrutiny.

The Commission has made it clear that no leniency will be tolerated, demanding a prompt and transparent inquiry and holding authorities accountable for any lapses.

LRPF has raised suspicion over the role of officials at the University of Madras, alleging that they neglected to conduct the mandatory inspection of Loyola College's campus as required under the established norms and regulations governing the grant and continuation of affiliation.

Tamil Nadu: Complaint filed against Registrar of Madras University for endorsing academic fraud by Loyola College

Reports: Kunti Surender#TamilNadu #LoyolaCollegehttps://t.co/JMgrxIjlea

— Organiser Weekly (@eOrganiser) March 27, 2025

In March 2025, LRPF filed the complaint with the Governor of Tamil Nadu, who serves as the Chancellor of the University of Madras. That complaint had similarly flagged unauthorized academic operations and religious bias, urging the Governor to revoke both autonomous status and affiliation granted to Loyola College.

In March 2025, LRPF filed the complaint with the Governor of Tamil Nadu, who serves as the Chancellor of the University of Madras. That complaint had similarly flagged unauthorized academic operations and religious bias, urging the Governor to revoke both autonomous status and affiliation granted to Loyola College.

Northeast News

NHRC member Priyank Kanoongo visits Meghalaya Temple, receives grievance memo from tribal forum

https://nenews.in/meghalaya/nhrc-member-priyank-kanoongo-visits-meghalaya-temple-receives-grievance-memo-from-tribal-forum/23171/

By Northeast News | April 8, 2025 in Meghalaya

Ampati: National Human Rights Commission (NHRC) member Priyank Kanoongo visited Chenga Benga Temple at Gandhipara in Meghalaya's South West Garo Hills on Monday (April 7), the concluding day of the Ashoka Ashtami celebrations.

During his visit, the Meghalaya Indigenous Minority Tribal Forum (MIMTF) submitted a memorandum to Kanoongo, detailing critical issues faced by the indigenous minority tribal communities in the state.

The memorandum highlighted grievances related to the state's job reservation policy, need for Assembly constituency delimitation, restrictions on Durga Puja celebrations, absence of a Hindu graveyard in Baghmara, issues in Esamati (South West Khasi Hills and East Khasi Hills), challenges concerning the Permanent Resident Certificate (PRC), and a demand for the creation of a Regional Council.

Thousands of devotees attended the four-day festival from April 4 to 7.

During the visit, Priyank Kanoongo also interacted with temple authorities, community leaders, and local residents, appreciating their role in preserving tradition and promoting communal harmony. Community members renewed their call for justice in connection with an alleged gang rape incident during last year's mela, urging the NHRC to ensure stronger security measures during future festivals.

Shri Priyank Kanoongo honoured Samuel Sangma, Officer-in-Charge of Garodoba ADC, with the 'Koch Sokatharay' for his sincerity and dedicated service.

While this year's celebrations were peaceful on the Meghalaya side, an incident of assault was reported from Assam. A devotee, Basudev Hajong from Poskunipara village in South Salmara-Mankachar district, was allegedly beaten en route the mela in Teporpara, Assam.

Kanoongo was accompanied by Vikash Kumar, Superintendent of Police; Zanera R Marak, District Social Welfare Officer; Tanweera M Sangma, District Child Protection Officer; Harkumar Hajong, retired IES officer, and Pramod Koch, MDC Dalu.

His visit was part of an official NHRC tour of the Northeastern states, including Assam, Meghalaya, and Tripura.

The NHRC member's visit reaffirmed the Commission's commitment to human rights, cultural inclusivity, and the concerns of minority tribal communities in the region.

Dainik Bhaskar

निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व उपायुक्त से शिकायत

https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/chaibasa/chakradharpur/news/complaint-to-national-human-rights-commission-and-deputy-commissioner-against-the-arbitrariness-of-private-schools-134800854.htm

चक्रधरपुर| मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ने चक्रधरपुर के निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ चैयरमैन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीबीएसई) दिल्ली के मुख्य सचिव झारखंड सरकार व जिला के उपायुक्त को मेल के माध्यम से शिकायत किया गया है। पत्र में कहा गया है कि चक्रधरपुर के तमाम छोटे-बड़े सभी विद्यालय के मैनेजमेंट बच्चों के अभिभावक से नियम के विपरित राशि का लूट कर रहे हैं। उदाहरण स्वरुप मंथली फीस के साथ वार्षिक फीस, रीएडमिशन फीस, स्कूल यूनिफॉर्म, महंगी किताबें, स्कूल डेवलपमेंट फीस है। निजी विद्यालयों में वैसे विद्यालय भी शामिल है जिसे सीबीएसई से मान्यता मिला हुआ है।

इस शिक्षा के नाम पर आम व्यक्ति का परिवार प्रभावित हो रहा है। शिक्षा के नाम पर लुट के लिए एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन करा कर ईमानदार पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम भेजा जाए। दोषी पाए जाने वाले निजी विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई हो। आम लोगों को बेहतर व सस्ते दर पर शिक्षा मिले इसकी समीक्षा के साथ कठोर कानून बने। सरकारी व सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त स्कूलों में कम से कम 20 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाए। सरकारी स्कूलों के तर्ज पर सभी सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय को सुविधा उपलब्ध कराया जाए। सभी सरकारी विद्यालय व सरकारी सहायता अल्पसंख्यक भाषाई विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाए।

Amar Ujala

दमोह फर्जी डॉक्टर: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की दूसरे दिन की सुनवाई शुरू, आज दो पीड़ितों को बयान होंगे दर्ज

https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/damoh/damoh-fake-doctor-national-human-rights-commission-s-investigation-begins-on-the-second-day-2025-04-08

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Tue, 08 Apr 2025 01:37 PM IST

सार

दमोह

हार्ट सर्जरी में सात मरीजों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम ने मंगलवार को दूसरे दिन की जांच सर्किट हाउस में की। टीम यहां दो पीड़ित की सुनावाई करेगी।

विस्तार

दमोह शहर के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम की हार्ट सर्जरी में सात मौतों के मामले में मंगलवार को दूसरे दिन फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पीड़ितों की सुनवाई की। टीम ने मामले की जांच के लिए पांच पीड़ित परिवारों को पत्र जारी कर बयान देने के लिए बुलाया था। पहले दिन सोमवार को तीन पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए थे। वहीं आज मंगलवार को दो पीड़ितों को बयान देने के लिए सर्किट हाउस बुलाया गया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम के सदस्य रिंकल कुमार, ब्रजवीर सिंह, राजेंद्र सिंह शामिल बयान ले रहे हैं। मीडिया को दूसरे दिन अंदर जाने से रोक दिया गया है। टीम के सदस्य भी मीडिया को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दे रहे।

पहले दिन पीड़ित कृष्ण पटेल, नवी कुरैशी और पूरन सिंह के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद शाम के समय टीम मिशन हॉस्पिटल जांच के लिए पहुंची। वहां देर रात तक टीम ने दस्तावेजों की जांच की। आयोग की टीम को यहां तीन दिन रुकना है।

ये है मामला

दमोह शहर के निजी मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की सर्जरी से सात हृदय मरीजों की मौत का मामला तब सामने आया, जब बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी ने मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से की। उन्होंने बताया एक-दो पीड़ित पक्ष हमारे संपर्क में आए थे। तब पता चला कि मिशन अस्पताल में बड़ी धांधली हुई है। सात हृदय रोगियों की मौत हुई है। जांच होगी तो उससे भी ज्यादा मौतें निकल सकती हैं। उन्होंने बताया कि मिशन अस्पताल में एन केम जॉन नाम का एक डॉक्टर है, जबकि इस नाम का असली डॉक्टर तो लंदन में है। उन्होंने सीएमएचओ मुकेश जैन से शिकायत की, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब 4 अप्रैल शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस मामले से जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'दमोह मध्यप्रदेश मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर द्वारा हृदय रोग के उपचार के नाम पर रोगियों के ऑपरेशन किए जाने से सात लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है। शिकायत के अनुसार उक्त मिशनरी अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से आच्छादित है, इसलिए सरकारी राशि का दुरुपयोग भी किया गया है।' इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जांच के आदेश दिए।

Nai Duniya

दमोह में 7 मरीजों की जान लेने वाला कथित डॉक्टर प्रयागराज से गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज से ली थी नौकरी

दमोह मिशन अस्पताल में फर्जी सर्जन नरेंद्र यादव द्वारा की गई 15 सर्जरी में सात मरीजों की मौत हुई। आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। उसने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाई थी। एनएचआरसी जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री ने फर्जी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/damoh-alleged-doctor-who-killed-7-patients-in-damoh-was-arrested-from-prayagraj-he-had-taken-the-job-with-fake-documents-8385383

By Anurag Mishra | Edited By: Anurag Mishra | Publish Date: Tue, 08 Apr 2025 04:28:54 PM (IST)

Updated Date: Tue, 08 Apr 2025 04:32:31 PM (IST)

HighLights

आरोपी नरेंद्र यादव प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया

एनएचआरसी टीम ने पीड़ितों के बयान दर्ज किए हैं

लंदन डॉक्टर का नाम उपयोग कर नौकरी हासिल की

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में इस साल जनवरी और फरवरी में 15 मरीजों की हृदय सर्जरी के बाद सात लोगों की असामयिक मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के मुख्य आरोपी कथित सर्जन डॉ. नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम को दमोह पुलिस ने सोमवार 7 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया।

उसके खिलाफ रविवार देर रात कोतवाली थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस बीच, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फर्जी डॉक्टरों की जांच के सख्त निर्देश दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी को दमोह लाया जा रहा है और मामले से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम ने भी इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है, जो पीड़ितों के बयान दर्ज कर रही है। यह मामला चिकित्सा क्षेत्र में लापरवाही और फर्जीवाड़े की गंभीर समस्या को उजागर करता है।

पुलिस ने प्रयागराज से दबोचा आरोपी

दमोह पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेंद्र यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि रविवार रात 2 बजे कोतवाली थाने में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. एमके जैन की शिकायत पर प्रकरण दर्ज हुआ था।

जांच में पता चला कि नरेंद्र यादव का पंजीयन मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में नहीं है और आंध्रप्रदेश मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर भी उसका नाम नहीं मिला। इसके बावजूद उसने मिशन अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी जटिल सर्जरी कीं, जिसके बाद सात मरीजों की मौत हो गई। पुलिस ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

फर्जी दस्तावेजों से हासिल की थी नौकरी

दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर को इस मामले की शिकायत मिलने के बाद उन्होंने सीएमएचओ को जांच के निर्देश दिए थे। जांच में पता चला कि नरेंद्र यादव ने लंदन के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. एन जॉन केम के नाम का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मिशन अस्पताल में नौकरी हासिल की थी।

अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि वह काम छोड़कर चला गया था। दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ कि जिन मरीजों की मौत हुई, उनकी सर्जरी नरेंद्र यादव ने ही की थी। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी कागजातों का सहारा लिया और मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया।

सात मरीजों की मौत

मिशन अस्पताल में हुई सात मौतों में से पांच पीड़ितों के नाम सामने आए हैं। इनमें सत्येंद्र सिंह राठौर (लाडनबाग हथना), रहीसा बेग (पुराना बाजार नंबर-2), इजरायल खान (डॉ. पसारी के पास), बुद्धा अहिरवाल (बरतलाई पटेरा) और मंगल सिंह राजपूत (बरतलाई पटेरा) शामिल हैं। सभी दमोह जिले के निवासी थे। इन मौतों के लिए नरेंद्र यादव को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

पीड़ितों के स्वजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उन्हें गुमराह किया और भारी फीस वसूलने के बाद बिना पोस्टमार्टम के शव सौंप दिए।

पीड़ितों के बयान दर्ज

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तीन सदस्यीय टीम ने सोमवार को दमोह पहुंचकर जांच शुरू की। टीम ने सर्किट हाउस में पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए, जिसमें पहले दिन तीन परिवारों ने अपनी बात रखी। शेष बयान मंगलवार को लिए जाएंगे। इसके बाद टीम देर शाम मिशन अस्पताल पहुंची और रात 9 बजे तक जांच जारी रखी।

अस्पताल स्टाफ से पूछताछ के साथ-साथ रिकॉर्ड की गहन पड़ताल की गई। एनएचआरसी अस्पताल की मान्यता, डॉक्टरों की नियुक्ति, और आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान जैसे पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि, टीम ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की।

सीएमएचओ की अनदेखी पर सवाल

दमोह बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी ने बताया कि नरेंद्र यादव ने जनवरी-फरवरी 2025 में 15 हृदय रोगियों की सर्जरी की थी, जिसमें सात की मौत हुई। कुछ मरीजों के स्वजनों ने फरवरी में सीएमएचओ डॉ. मुकेश जैन से शिकायत की थी, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मार्च में एनएचआरसी से शिकायत की गई, जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया। तिवारी ने सीएमएचओ की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और इसकी जांच की मांग की है।

तेलंगाना में भी फर्जीवाड़े का इतिहास

आरोपी नरेंद्र यादव का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके आधार कार्ड के मुताबिक वह देहरादून का निवासी है और उसका नाम नरेंद्र जॉन केम है। वर्ष 2019 में तेलंगाना के रचकोंडा में उसने ब्राउंडवाल्ड हॉस्पिटल में फर्जीवाड़ा किया था, जहां वह चेयरमैन के पद पर था।

उसकी पत्नी दिव्या रावत के साथ मिलकर उसने वहां भी धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। दमोह में वह गुजरात में पंजीकृत वाहन का इस्तेमाल कर रहा था, जो उसके संदिग्ध व्यवहार को और उजागर करता है।

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार दोपहर फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था में खामियों को उजागर किया है, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गई है। यह मामला न केवल मिशन अस्पताल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को भी कठघरे में खड़ा करता है।

Patrika News

फर्जी डॉक्टर के खिलाफ पहले होती जांच तो बच सकती थी 7 लोगों की जान

Mission Hospital Case : दमोह के मिशन अस्पताल केस, अगर फर्जी डॉक्टर के खिलाफ पहले होती जांच तो 7 लोगों की जान बच सकती थी।

https://www.patrika.com/damoh-news/mission-hospital-case-investigation-against-fake-doctor-had-done-earlier-7-lives-could-saved-19516607

दमोह•Apr 08, 2025 / 02:22 pm•

Faiz

Mission Hospital Case : मध्य प्रदेश के दमोह के मिशन अस्पताल में 7 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट एन जॉन केम उर्फ डॉ. नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र की टाउनशिप में छिपा बैठा था। दमोह साइबर सेल ने उसका मोबाइल चालू होते ही लोकेशन ट्रेस कर दबोचा है। पुलिस आरोपी को रात 11.30 बजे दमोह लाई थी। वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी दमोह पहुंची और ऑपरेशन के चलते जान गवाने वाले 7 मरीजों के परिजन के साथ-साथ बचने वाले एक मरीज के परिजन के बयान दर्ज कराए। वहीं, कलेक्टर, एसपी व सीएमएचओ के बयान भी लिए गए।

इसी बीच पत्रिका ने छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के बेटे प्रो. प्रदीप शुक्ल से भी फर्जी डॉ. के संबंध में बातचीत की। क्योंकि, इस फर्जी डॉक्टर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की भी एंजियोप्लास्टी की थी। बेटे प्रदीप शुक्ल को संदेह था कि, उसी के बाद हालत बिगड़ने के कारण उनके पिता की मौत हो गई थी। मानवाधिकार आयोग द्वारा लिए गए पीड़ित परिजन के बयानों और पत्रिका की राजेन्द्र शुक्ल के बेटे से हुई बातचीत से ये प्रतीत हुआ है कि, अगर फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के खिलाफ पहले ही जांच कर ली जाती तो शायद आज उन 7 लोगों की जान किसी फर्जी डॉक्टर के हाथों न जाती।

पूर्व विस अध्यक्ष के बेटे प्रो. प्रदीप की जुबानी

बिलासपुर में पत्रिका से बातचीत के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल के बेटे प्रोफेसर प्रदीप शुक्ल ने बताया कि, '2 अगस्त 2006 की बात है। मेरे बाबूजी राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल की तबीयत खराब होने पर शहर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। वहां बाबूजी का इलाज डॉ. राजीव राठी करते थे। लेकिन, वे अपोलो छोड़कर दूसरी जगह चले गए। उनकी जगह डॉ. नरेन्द्र विक्रमादित्य यादव ने उनकी एंजियोप्लास्टी की थी। उस समय डॉ. नरेन्द्र के बारे में बताया गया था कि, वे मध्य भारत में लेजर से हार्ट का ऑपरेशन करने वाले सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। सर्जरी के कुछ घंटे के बाद बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें करीब 18 दिन तक वेंटीलेटर पर आईसीयू में रखा गया। लेकिन प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करते ही 20 अगस्त 2006 को बाबूजी नहीं रहे।'

प्रो. प्रदीप शुक्ल ने आगे कहा- 'तभी मुझे डॉ. विक्रमादित्य पर शक हुआ था। इसके बाद अपोलो में भी इस डॉक्टर द्वारा की गई सर्जरी के बाद कुछ और मौतों की खबरे सामने आई थी। अपोलो का स्टाफ भी इस

फर्जी डॉक्टर को पसंद नहीं करता था। वो यहां अकेला रहता था। इस बीच डॉ. नरेन्द्र अपोलो से फरार हो गया। उस दौरान मैंने आरटीआई लगाकर उनकी डिग्री की जानकारी मांगी थी, लेकिन मुझे नहीं दी गई। मैं उन्हें गूगल आदि पर ढूंढ रहा था, लेकिन अब जब दमोह मिशन हॉस्पिटल में 7 मौतों के पीछे इस डॉक्टर का नाम और फोटो सामने आया तो मेरे सामने 2006 का वो दृश्य आ गया। काश, उस समय फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेन्द्र जॉन केम के खिलाफ कड़ी जांच हुई होती तो आज दमोह समेत इतनी जगहों पर इस तरह मौतें नहीं हुई होतीं। ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।'

फर्जी डॉ. ने बताए तीन, पर असल में दो ब्लाकेज थे- कृष्णा पटेल

दमोह में मानवाधिकार आयोग को बयान दर्ज कराने दमोह के सिविल वार्ड निवासी कृष्णा पटेल भी आए। डॉ. एन जॉन केम ने जिन 8 मरीजों का इलाज किया था, उनमें से इस युवक के दादा ही बचे थे। 31 जनवरी को कृष्णा अपने दादा आशाराम पटेल को लेकर मिशन अस्पताल पहुंते थे। वहां, कार्डियोलॉजिस्ट एन जॉन केम ने उन्हें तीन ब्लॉकेज बताते हुए ओपन हार्ट सर्जरी कराने को कहा। लेकिन, जब उनसे कुछ सवाल पूछे तो वो भड़क गए। हालांकि, उन्होंने वहां सिर्फ दादा की एंजियोप्लास्टी ही कराई थी। डॉक्टर से संतुष्ट न होने के चलते जब उन्होंने बाहर ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए डॉ. केम से एंजियोप्लास्टी की सीडी मांगी तो उन्होंने पहले तो देने से इंकार कर दिया। बमुश्किल उन्हें सीडी दी तो पता चला कि वो सीडी खाली थी।

इसके बाद जबलपुर में जांच कराई तो पता चला कि दादा के तीन नहीं दो ब्लॉकेज निकले। पटेल ने बताया, डॉ. केम पहले नरसिंहपुर के एक निजी अस्पताल में था, जहां भी तीन लोगों की इसी तरह इलाज के दौरान मौतें हुई थीं। पटेल ने बताया कि, फरवरी में उसने कलेक्टर को इस संबंध में लिखित शिकायत की थी। उस दौरान जांच का आश्वासन तो मिला था, पर बाद में कोई अपडेट ही नहीं दिया गया।

'मुझे मुआवजा नहीं डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई चाहिए'

नबी कुरैशी ने मानवाधिकार टीम को मां रहीसा बेगम के इलाज के दस्तावेज दिए। टीम ने पूछा-क्या चाहते हो। नबी ने कहा, मुआवजा नहीं चाहिए। मां को नहीं बचा सका, पर उम्मीद करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषी पर कड़ी कार्रवाई हो।

ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार

मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सख्त कार्रवाई होगी। कोई कमी, गलती या तथ्य छिपाए हैं तो सरकार संज्ञान लेगी। सीएम ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को गहन जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।